वर्ष-10, अंक-10, जुलाई-2025

मूल्य: ₹20

# वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

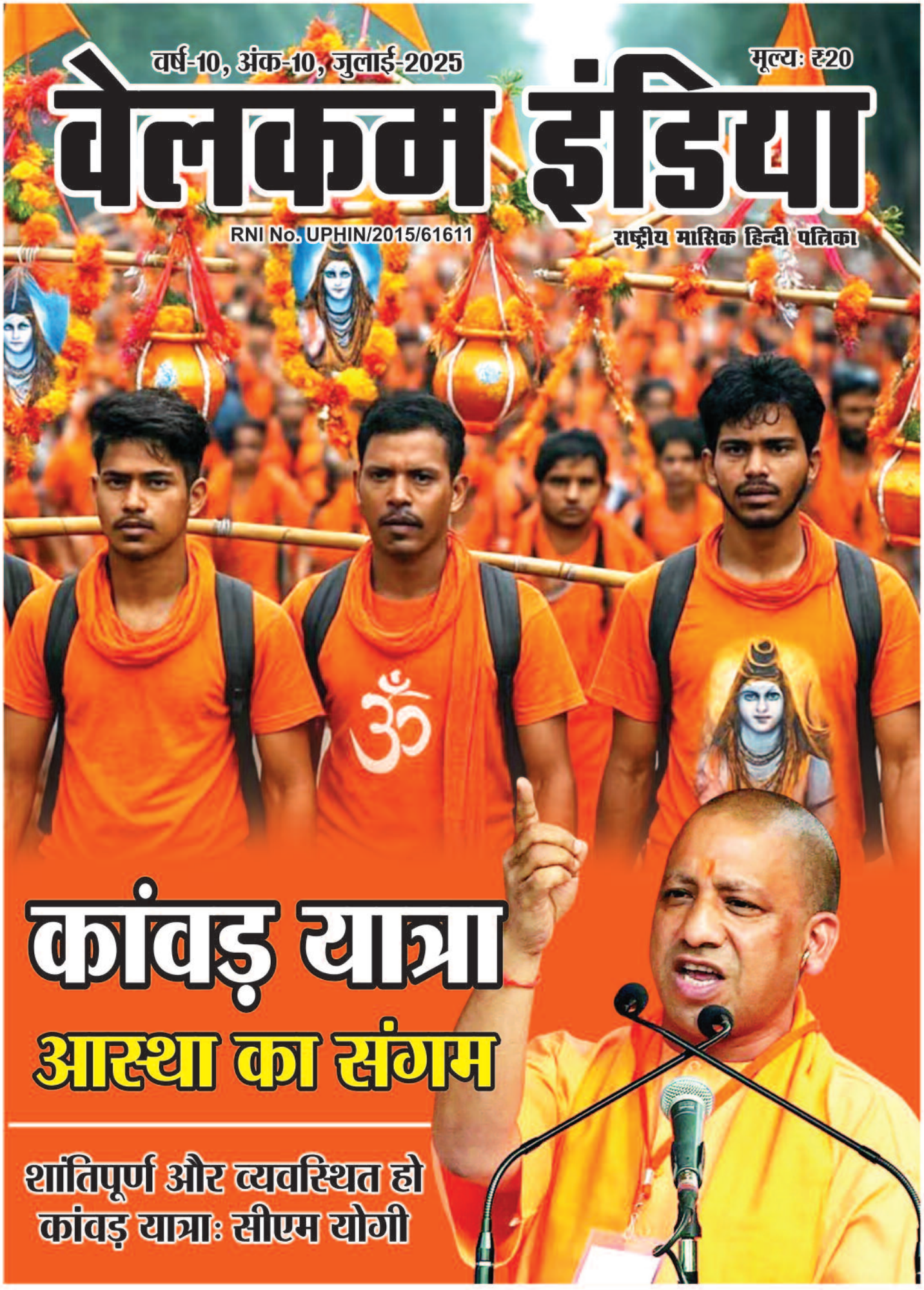

## कांवड़ यात्रा

## आस्था का संगम

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो
कांवड़ यात्रा: सीएम योगी

मिशन रोज़गार

| 8.5 लाख+ | 3.75 लाख+ | 2 करोड़+ |
|---|---|---|
| सरकारी नौकरी | संविदा पर नौकरी | निजी क्षेत्र/ एमएसएमई में रोजगार |

## उत्तर प्रदेश में
# आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में महिला शक्ति

## 12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन

| 27,178 | 10,378 | 78 | 1,596 |
|---|---|---|---|
| महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति | महिला बीटों का आवंटन | महिला पुलिस परामर्श केन्द्र | महिला हेल्प डेस्क की स्थापना |

- प्रत्येक जनपद में महिला थाने के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की तैनाती
- लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन

**काम दमदार डबल इंजन सरकार**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

# अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 10 अंक- 10

जुलाई-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी
पेज-28

पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा ने सफलता के नए कीर्तिमान रचे
पेज 03

जांबाज आईपीएस ध्रुवल जायसवालः माफियाओं व हिस्ट्रीशटर में खौफ का दूसरा नाम
पेज 05

कथावाचक कांड की आड़ में सनातन पर हमला
पेज 14

अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने किए 7 परीक्षण...
पेज 22

मिस वर्ल्ड का खिताब जीत इंडस्ट्री में आईं ये हीरोइन
पेज 52

5 बल्लेबाज जिन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन
पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

# भारत के तीन दुश्मन

ललित कुमार
सम्पादक

भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक महत्वपूर्ण पक्ष का रहस्योद्घाटन किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रत्यक्ष संघर्ष लड़ा था, लेकिन चीन और तुर्किए भी भारत के 'प्रत्यक्ष दुश्मन' की भूमिका में थे। चीन ने पाकिस्तान की हरसंभव मदद की और खुफिया सूचनाएं भी साझा कीं। चीन ने सेटेलाइट और अन्य माध्यमों के जरिए खुफिया लीड्स हासिल कीं कि भारत की सैन्य तैयारियां कैसी और क्या हैं? कहां, कौनसा लड़ाकू विमान, मिसाइलों सहित, मौजूद है और कभी भी हमला कर सकता है। चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को 'लाइव लैब' की तरह खूब इस्तेमाल किया और अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों की टेस्टिंग की। बेहद संवेदनशील पक्ष यह था कि जब दोनों देशों के डीजीएमओ में बातचीत चल रही थी, तो पाक डीजीएमओ ने हमारे समकक्ष अधिकारी को कहा था कि भारत का एक अहम वेक्टर तैयार है। भारत पहले उसे हटा कर पीछे करे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सवाल उठाया कि इतनी महीन और सटीक जानकारी पाक डीजीएमओ को कहां से मिली? जाहिर है कि ऐसे खुफिया इनपुट चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे। बेशक यह चीन की प्राचीन सैन्य रणनीति '36 स्टैटेजम्स' में से एक थी। इसके मायने हैं-'किराए की छुरी से वार करना।' अर्थात इस रणनीति के तहत चीन ने, भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को 'किराए की छुरी' के तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह 'ऑपरेशन सिंदूर' संघर्ष के दौरान भारत को एक साथ तीन मोर्चों-पाकिस्तान, चीन, तुर्किए-पर लडऩा पड़ा। ये तीनों ही देश 'भारत के दुश्मन' साबित हुए और भविष्य में भारत का विरोध करते रहेंगे, यह बिल्कुल तय है। लिहाजा हमें अपनी सैन्य तैयारियां उसी स्तर की करनी होंगी। सेना ऐसा कर भी रही है। पाकिस्तान के पास जो हथियार, विमान हैं, उनमें से करीब 81 फीसदी चीन ने उसे बेचे अथवा उधार पर मुहैया कराए हैं। तुर्किए ने पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन ही नहीं दिए, बल्कि उसके लड़ाकों और पायलटों ने भी पाकिस्तान की ओर से संघर्ष में शिरकत की, लेकिन न तो चीन और न ही तुर्किए संघर्ष की दशा और दिशा बदल सके। भारत के हवाई हमलों ने चीन की मिसाइलें और तुर्किए के ड्रोन, हवा में ही, चकनाचूर कर दिए। पाकिस्तान के जितने एयरबेस और उधार के लड़ाकू विमानों को हमारी सेना ने 'मिट्टी-मलबा' किया, उसके खुलासे दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान सैन्य रूप से कब तक हमलावर की स्थिति में लौट पाएगा, इसमें सालों भी लग सकते हैं। उप सेना प्रमुख ने ये तमाम खुलासे उद्योगपतियों के संगठन 'फिक्की' के मंच से किए। उन्होंने वह मंच ही क्यों चुना? क्या निवेश का आह्वान किया जाना था? उप सेना प्रमुख ने ही लगभग दो माह बाद यह रहस्योद्घाटन क्यों किया? क्या सरकार के शीर्ष स्तरों से उन्हें यह काम करने का दायित्व सौंपा गया? कई सवाल हैं। भारतीय सेना तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ी, यह खुलासा मीडिया के जरिए देश के सामने आ चुका था। देश के दुश्मन तीन देश ही नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश में तुर्किए और चीन नए रणनीतिक मोर्चे बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। आज का बांग्लादेश भारत-विरोधी है। क्या भविष्य में भारत को कई मोर्चों पर लड़ाई लडऩी पड़ सकती है? क्या हमारी उतनी बहुआयामी सैन्य तैयारियां हैं? यदि दुश्मन भविष्य में सघन आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाते हैं, तो क्या उतने व्यापक स्तर पर हमारे पास बंकर आदि की व्यवस्था है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान और पीओके में किए गए हमलों की योजना ठोस डाटा पर आधारित थी। भारत ने 21 संभावित टारगेट चिह्नित किए थे। उनमें से 9 को अंतिम समय में कार्रवाई के लिए चुना गया। इस दौरान तकनीक और मानव खुफिया से जुटाई जानकारी इस्तेमाल की गई। उप सेना प्रमुख ने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली की अहमियत को उजागर कर दिया। चूंकि चीन खुफिया सूचनाओं के संदर्भ में पाकिस्तान की मदद भविष्य में भी करेगा, ऐसे में हमें मजबूत और आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है, जो दुश्मन की निगरानी और उसके हमलों को रोक सके। बहरहाल भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती मिल रही है, लेकिन बड़े देश हमें समर्थन भी कर रहे हैं। भविष्य के लिए भारत को बड़ी तैयारियां करनी हैं।

सेना ऐसा कर भी रही है। पाकिस्तान के पास जो हथियार, विमान हैं, उनमें से करीब 81 फीसदी चीन ने उसे बेचे अथवा उधार पर मुहैया कराए हैं। तुर्किए ने पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन ही नहीं दिए, बल्कि उसके लड़ाकों और पायलटों ने भी पाकिस्तान की ओर से संघर्ष में शिरकत की, लेकिन न तो चीन और न ही तुर्किए संघर्ष की दशा और दिशा बदल सके। भारत के हवाई हमलों ने चीन की मिसाइलें और तुर्किए के ड्रोन, हवा में ही, चकनाचूर कर दिए।

# G7 के मुकाबले ब्रिक्स देशों की जवाबी रणनीति से अमेरिकी चिढ़ के अंतरराष्ट्रीय मायने






चरण सिंह

अमेरिकी नेतृत्व वाले जी-सेवन के मुकाबले ब्रिक्स देशों की जवाबी रणनीति और उसके बारे में सम्बन्धित देशों के द्वारा ना-नुकुर करते रहने से विफरे अमेरिकी चिढ़ के अंतरराष्ट्रीय मायने स्पष्ट हैं और ये देर-सबेर अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाले हैं। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ब्रेक के बाद फिर से दुनिया में हलचल मचाने लगा है, क्योंकि गत सोमवार को ही उन्होंने अपने मित्र जापान-साउथ कोरिया समेत 14 देशों पर फ्रेश टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

वहीं इससे पहले ब्रिक्स पर निशाना साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिकी नीतियों के खिलाफ जाएगा, उस पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप की इस चेतावनी को लेकर ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों ने कड़ी आलोचना की है। इसलिए स्वाभाविक सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, जिसे लेकर ब्रिक्स देश ट्रंप के टारगेट पर हैं और इन अतिरिक्त टैरिफ का इन देशों पर क्या असर होगा, जिसमें उसका कथित मित्र भारत भी शामिल है?

उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। दरअसल, इसका नाम भी इन्हीं पांच देशों के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन बढ़ाना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिय और संयुक्त अरब अमीरात को भी संगठन में शामिल किया गया था। वैसे तो सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है, हालांकि अभी तक वह आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। शायद अपनी अमेरिकी करीबियों के चलते!

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 अप्रैल को ही दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में इसे 90 दिन के लिए रोक दिया था। इस छूट की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने वाली थी, लिहाजा इसे 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया है। वहीं, इससे पहले सोमवार 7 जुलाई को ही ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना शुरू कर दिया और जापान-साउथ कोरिया के अलावा म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर 25 फीसदी से 40 फीसदी तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स देशों के लिए एक चेतावनी भी जारी की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंफ ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी-अमेरिकन पॉलिसी का समर्थन करेंगे, उन पर 10 फीसदी का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अमेरिका की इस नीति में किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। इशारा स्पष्ट इशारा भारत की ओर था। यहां बता दें कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में

6-7 जुलाई को संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक घोषणापत्र में यूएस टैरिफ की आलोचना की गई थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

इसलिए सवाल दर सवाल उभरता है कि आखिर क्या टैरिफ की आलोचना ही एकमात्र कारण है, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंफ ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी कुछ ठोस वजह हैं। यदि ऐसा है तो क्या क्या है, यह जानना हर किसी के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस साल अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट और बीते कुछ समय में यूएस इकोनॉमी में सुस्ती के कारण ट्रंप को ऐसा लगता है कि हर कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। वहीं, दूसरा बड़ा कारण दुनिया के तमाम बड़े देशों द्वारा डॉलर के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना भी इसके पीछे की वजह समझा जा सकता है।

इस बात का एक बड़ा उदाहरण देखें, तो स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल और आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ही ट्रेड करते रहे हैं। यही नहीं 2022 में तो रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रस्ताव भी दिया था। जिससे अमेरिका का चिढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि डॉलर पर बड़े देशों की निर्भरता कम होना अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसको लेकर ट्रंप की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं, जब से अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया है और ईरान (2012 में) के अलावा रूस (2022 में) को विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार (रहक्क्रछ्ठ) सोसायटी से बाहर रखा गया है, तभी से दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है।

सच कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को ऐसे ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ब्रिक्स अब वैश्विक आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। अब अगर वे वैश्विक व्यापार में इस समूह में शामिल बड़े देशों द्वारा डॉलर के उपयोग को कम किया जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे भी डॉलर में इस साल येन-यूरो के मुकाबले 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है और ये बीते दिनों 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

वहीं, अमेरिका की एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनसियो लूला दा सिल्वा ने सख्त तेवर दिखाए हैं और 10% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है और हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा कि ब्रिक्स अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के नए तरीके तलाश रहा है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि कुछ बड़े देश/लोग खुद में असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं चीन ने भी स्पष्ट कहा है कि ब्रिक्स किसी भी देश के खिलाफ नहीं है।

सनद रहे कि इससे पहले साल 2025 की शुरूआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इसमें शामिल देश वैश्विक व्यापार में डॉलर की भूमिका को चुनौती देंगे, तो फिर उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ताजा चेतावनी सिर्फ 10 फीसदी की है, जो सुकून की बात है। इस बीच एक अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट की मानें, तो इसमें कहा गया है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन सभी ब्रिक्स देशों पर तत्काल 10% टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि अगर कोई भी देश ऐसे कदम उठाता है जिसे वह अमेरिका विरोधी मानता है, तो उसे इस तरह की अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंफ की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स के उस घोषणापत्र पर साइन किए हैं, जिसमें अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई। इसलिए ये सवाल भी अहम हो जाता है क्योंकि टैरिफ युद्ध के बीच इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। हालांकि, ट्रंप ने सोमवार को 14 देशों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के करीब हैं। भारत के लिए यह उम्मीद की किरण है।

हालांकि, लोकतंत्र के कथित पहरूए और जनद्रोही पूंजीवाद के कट्टर समर्थक अमेरिका को यदि समझना हो तो उसकी उन नीतियों पर गौर करना लाजिमी है, जिसके बल पर वह पूरी दुनिया को हांकता रहता है।

कभी तकनीकी क्रांति और कभी आर्थिक लाभ हेतु डॉलर डिप्लोमेसी का सहारा लेने वाला अमेरिका दुनिया भर में पहले झगड़ा लगाने और फिर पंचायती करके लाभ कमाने का आदी रहा है। इसलिए उसकी नीतियों को वक्त वक्त पर अंतरराष्ट्रीय चुनौती भी मिलती रही हैं। भूमंडलीकरण और खुली अर्थव्यवस्था का उन्नायक कब और कैसे मानवता विरोधी खलनायक बन गया, जनशोध का विषय है।

जानकार बताते हैं कि ₹मेक अमेरिका ग्रेट अगेन₹ का नारा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण अमेरिकी देशों का असरदार सरदार समझा जाता है, जो दुनिया को दर्द बांटकर उसके कारोबारी सफलता हासिल करने के यत्न दर यत्न का घिनौना समर्थन करते रहते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सोवियत संघ (मौजूदा रूस के पड़ोसी देशों का संघ गणराज्य) को चुनौती देकर हथियारों, ड्रग्स सिंडिकेट और कारोबारी सिंडिकेट की आड़ में मानवता को तबाह करने का आरोपी अमेरिका, जब 21वीं के पूर्वार्द्ध में चीन से अनर्गल प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों के मन में सवाल उपजा की, आखिर रूस और भारत के खिलाफ तथा पाकिस्तान के समर्थन हेतु अमेरिका ने जिस चीन में औद्योगिक विकास की रफ्तार दी, आखिर अब वह उसी चीन को अपना कारोबारी दुश्मन क्यों बना बैठा है?

# जांबाज आईपीएस धवल जायसवाल

## माफियाओं व हिस्ट्रीशटर में खौफ का दूसरा नाम

ललित कुमार

आईपीएस धवल जायसवाल की गिनते उत्तरप्रदेश में जांबाज व तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। वे अब तक जिस भी जनपद में तैनात रहे, वहां के माफियाओं व हिस्ट्रीशीटर्स की शामत बन कर रहे। धवल जायसवाल को माफियाओं व हिस्ट्रीशटर में खौफ पर्याय माना जाता है। वे अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए डीजीपी के सिल्वर मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही 2019 में कुंभ सेवा मेडल और डीजीपी के प्लैटिनम और गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं।

करीब एक दशक के अपने शानदार कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश भर में कड़क कार्रवाई करके दर्जनों माफियाओं की कमर तोड़ी, वहीं करीब डेढ़ सौ बदमाशों का एन्काउंटर किया। धवल जायसवाल जहां तैनात रहते हैं, वे कानून-व्यवस्था के मामले में किसी के दबाव में नहीं आते। उन्होंने मेरठ अपनी तैनाती के दौरान सबसे बड़े मिलावटी तेल गैंग का पदार्फाश कर माफियाओं को उनकी असली जगह जेल दिखाकर अपने बुलंद हौंसला की बानगी दिखायी थी।

2016 बैच के आईपीएस धवल जायसवाल इस समय गाजियाबाद में डीसीपी सिटी के तौर पर तैनात हैं। अभी उन्हें यहां तैनाती के कुछ ही माह हुए हैं, लेकिन अल्प समय में ही उनकी गिनती बहुत ही लोकप्रिय अधिकारियों में होती है। गाजियाबाद में मिली तैनाती से पहले वे चित्रकूट, कुशीनगर और फतेहपुर के एसपी रहे।

मेरठ, प्रयागराज और उन्नाव में रहे। लेकिन अपनी तैनाती के दौरान जहां भी वे रहे, अपराधियों के प्रति उनकी सख्ती काबिले तारीफ रही, जबकि आम जनता के प्रति उनका व्यवहार सदैव सरल व सहज होने से वे बहुत जल्द लोगों के चहेते पुलिस अधिकारी बन जाते हैं। उनका इस सहजता का एक कारण उनकी पृष्ठभूमि माना जाता है। अपराधियों के लिए वे कड़क मिजाज वाले आला पुलिस अधिकारी हैं, सामान्य लोगों के लिए उनका व्यवहार बहुत की शालीन व मधुर रहता है।

भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले धवल जायसवाल दिल्ली के एक कॉलेज व विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आईपीएस बनने पर उन्होंने दो बार प्रोफेसर की नौकरी से त्याग पत्र दिया। इसलिए उनके व्यवहार में सौम्यता का भाव स्वाभाविकक है। बाल्य अवस्था में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनकी मां ही उनके लिए सब कुछ थीं। उनकी माता जी की इच्छी थी कि वे आईपीएस बने तो एक आज्ञाकारी पुत्र ने न केवल प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, बल्कि बिना कोचिंग यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करके खुद को उच्च स्तरीय बौद्धिकता का सिद्ध किया। साथ ही उच्च आदर्शो के साथ लक्ष्य के प्रति संजीदगी के साथ प्रयास करके स्वाध्याय से सफलता प्राप्त करने के मानदंडो को भी स्थापित किया। प्रोफेसर से आईपीएस बनकर उन्होंने अपनी मां का सपना भी पूरा किया।

### सुलतानपुर में व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं धवल जायसवाल

उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर शहर के नगर एरिया चौक में व्यवसायी नंद किशोर जायसवाल के घर 1988 को जन्मे धवल जायसवाल के पिता एक हादसे में चल बसे थे। तब वे महज 5 साल के थे। उनकी माता जी माया देवी के ही उन्हें पाला पोसा और अच्छे संस्कार दिये। उनकी प्रारंभिक शिक्षा

सुल्तानपुर में हुई। 2004 में सीबीएसई बोर्ड से हाईस्कूल व 2006 में इंटर पास करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्रयागराज चले गये। 2009 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। इसके बाद जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी दिल्ली से हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल के साथ एमए की परीक्षा पास की।

## पहले कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने

धवल जायसवाल एक साल तक कमला नेहरु कॉलेज, नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। इसके बाद उनका चयन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर हुआ। उसी समय उन्होंने एम.फिल भी किया। वे नौकरी के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे। जब उन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया तो उन्हें खुद पर विश्वास हो गया कि वे यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास व मेहनत के बल पर उन्होंने आईपीएस बनकर यह करके भी दिखाया।

## मां को मानते हैं अपना आदर्श व प्रेरणास्रोत

आईपीएस धवल जायसवाल अपनी माता जी माया देवी को अपना आदर्श व प्रेरणास्रोत मानते हैं। उनका कहना है कि पिताश्री के गुजर जाने के बाद मां ने हौंसला देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मां चाहती थीं कि मैं बड़ा पुलिस अफसर बनूं। इसलिए उनकी भावना की कद्र करते हुए सुल्तानपुर छोड़कर प्रयागराज और फिर दिल्ली पढ़ने आया। एक बार मां ने कहा था कि मेहनत से पढ़ना, तुम्हें अपना लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मां की ही आशीर्वाद है कि मैं उनकी इच्छा पूरा करने में सफल रहा और आईपीएस बना। हालांकि मैं स्वयं भी पुलिस अफसर ही बनना चाहता था, लेकिन इससे लिए हमेशा माता जी ने प्रेरित किया और उनकी आशीष से ही आज इस मुकाम पर हूं।

## बतौर आईपीएस अधिकारी पहली पोस्टिंग प्रयागराज में हुई थी

गाजियाबाद में डीसीपी सिटी के रुप में तैनात धवल जायसवाल का कहना है कि आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी 2018 में पहली पोस्टिंग प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज में उन्होंने बतौर एसीपी व्यवसायिक बारीकी से समझा व सीखा। प्रयागराज में उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया और एक ही दिन में एक हजार किलो मादक पदार्थ पकड़कर आधा दर्जन से अधिक तस्करों को जेल भेजा। उन्होंने 2019 का कुंभ मेला भी सकुशल संपन्न कराया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया।

## अब तक के करियर की उपलब्धियां

धवल जायसवाल अगस्त, 2019 मेरठ में सहायक पुलिस अधीक्षक के रुप में टीपीनगर में केमिकल या मिलावटी तेल स्टॉक का पकड़कर सात लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर भी मिलावट की जांच कराई।

फरवरी, 2022 में बतौर चित्रकूट एसपी उन्होने 9 साल के बच्चे कन्हैया की लापता एक ड्रम में बच्चे का शव मिलने का मामले का खुलासा किया। इस मामले के मृतक के निसंतान चाचा भुल्लू और चाची उर्मिला द्वारा बच्चे की बलि देने का खुलासा किया था। चित्रकूट में ही 2022 का विधानसभा चुनाव शराब तस्करी पर रोक लगाते हुए 50 से ज्यादा लोगों को जेल भिजवाया था।

कुशीनगर में 96 अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। गोकशी रोकने लिए पुलिस ने गांव-गांव अभियान चलाया। गोकशी करने वाले 70 लोगों पर गैंगस्टर लगाया। यहां देहात क्षेत्र के जंगल में दिन में रेकी के बाद रात में गोकशी की जाती थी। इस मामले में लिप्त जिले भर से 150 अपराधियों को जेल भेजा गया।

## तिहरे हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे में कर दिया था

अप्रैल 2025 में फतेहपुर एसपी के रुप में हथगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव में प्रधान के दो बेटों विनोद, अनूप सिंह और पौत्र की हत्या कर दी गई। इस तिहरे हत्याकांड को सॉल्व करने के लिए पुलिस की 8 टीमें लगाईं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा।

धवल जायसवाल बताते हैं कि फतेहपुर में गोकशी रोकने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया गया। पुलिस ने 18 अपराधियों को पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। 75 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। जिले के सबसे बड़े माफियाओं में शामिल रहे हाजी रजा की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। हाजी रजा ने ही प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके अलावा शराब माफिया मोइन की भी 16 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त की थी।

# मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

**भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए।**

राहुल अग्रवाल

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट

किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि 'जो सरकार करे, उसका विरोध करो', चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना। लेकिन जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह यह है कि इस पूरी कवायद के दौरान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर इसका विरोध करता नजर आया, भले ही मामला राष्ट्रहित और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हो। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने, फर्जी वोटरों की छंटनी, और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक शुद्धिकरण था। यह सुधार न केवल चुनावों को पारदर्शी बनाता है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। परन्तु कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इसे जातीय आंकड़ों, राजनीतिक संतुलन और चुनावी गणित से जोड़कर कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण संविधान सम्मत प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को न केवल वैध बताया, बल्कि उसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी बताया। यह फैसला यह भी दशार्ता है कि अब समय आ गया है जब चुनावी ईमानदारी को राजनीतिक शोरगुल और वोट बैंक की राजनीति के शोर में दबाया नहीं जा सकता। विपक्ष की प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित होती जा रही है, चाहे मुद्दा हो आर्थिक सुधार का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, या अब मतदाता सूची सुधार का। प्रश्न यह उठता है कि क्या हर सुधार प्रक्रिया, चाहे वह कितनी भी लोकतांत्रिक या पारदर्शी हो, विपक्ष के लिए मात्र एक राजनैतिक खतरा है? विपक्ष का यह रवैया यह दशार्ता है कि उसे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम और अपनी राजनीतिक गणनाओं पर भरोसा अधिक है।

**मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है।**

एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना। यदि कोई सुधार प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक भी फर्जी वोटर सूची में न हो, कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची बने, तो फिर उसका विरोध क्यों? विपक्ष इस डर से ग्रस्त है कि यदि मतदाता सूची साफ-सुथरी हो गई, तो उनके कथित परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकते हैं। उन्हें डर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यह तर्क लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। लोकतंत्र 'जो है, उसे प्रतिबिंबित करे', न कि 'जो चाहिए, उसे निर्मित करे'।

# एससीओ में रक्षामंत्री का चीन-पाक को कड़ा संदेश

भारत विश्व स्तर पर इस कोशिश में लगा रहता है कि आतंकवाद का दबाव कम हो, दुनिया आतंकमुक्त बने, निर्दोष लोगों की क्रूर आतंकी हत्याओं पर विराम लगे, पर दुर्भाग्य से दुनिया में अनेक देश अपना राजनीतिक नफा-नुकसान देखकर ही इस पर अपना रुख तय करते हैं।

रवि जैन

भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के पोर्टे सिटी किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त घोषणापत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर न केवल पाकिस्तान और चीन को नये भारत का कड़ा संदेश दिया, बल्कि दुनिया को भी जता दिया कि भारत आतंकवाद को पोषित एवं पल्लवित करने वाले देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई निरन्तर जारी रखेगा। घोषणापत्र में बलोचिस्तान की चर्चा की गई थी किन्तु पहलगाम के क्रूर आतंकवादी हमले जिनमें धर्म पूछकर 26 लोगों को मारे जाने का कोई विवरण नहीं था। भारत की आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड के विरुद्ध इस दृढ़ता एवं साहसिकता की चर्चा विश्वव्यापी हो रही है। भारत ने विश्व को आगाह कर दिया है कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। राजनाथ सिंह के अडिगता एवं असहमति के इस कदम से एससीओ के रक्षामंत्रियों का सम्मेलन बिना संयुक्त वक्तव्य जारी किये ही समाप्त हो गया, जो पाकिस्तान एवं चीन के मुंह पर करारा तमाचा है। ऐसा होना भारत की ही जीत है और चीन-पाकिस्तान के लिये शर्मसार होने की घटना है। विशेषतः इस घटनाक्रम से चीन की बदनीयत एक बार फिर से उजागर हो गई है।

भारत विश्व स्तर पर इस कोशिश में लगा रहता है कि आतंकवाद का दबाव कम हो, दुनिया आतंकमुक्त बने, निर्दोष लोगों की क्रूर आतंकी हत्याओं पर विराम लगे, पर दुर्भाग्य से दुनिया में अनेक देश अपना राजनीतिक नफा-नुकसान देखकर ही इस पर अपना रुख तय करते हैं। वास्तव में एससीओ की बैठक में भी यही हुआ है। त्रासद विडंबना है कि एससीओ में शामिल देशों ने भारत में पडोसी देश पाक की आतंक घटनाओं पर विसंगतिपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया। वास्तव में, यह एक और प्रमाण है कि पाक पोषित आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बीच,

अमरनाथ यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवार को उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सोचने पर मजबूर करती है। पाक की आतंकी हरकतें रूक नहीं रही है, अमरनाथ यात्रा पहले ही आतंकियों के निशाने पर रही है और इस बार भी आतंकियों के निशाने पर है, विगत तीन दशक से तनाव की स्थिति में ही अमरनाथ यात्रा हो रही है। सुरक्षा बल शांतिपूर्ण यात्रा के लिए प्रयासरत हैं लेकिन एससीओ जैसे संगठनों को पाक को सख्त हिदायत देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में पाक समर्थित आतंकवाद रूकना चाहिए।

निश्चित ही एससीओ सम्मेलन में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एक निडर एवं साहसिक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने की भारत की नई नीति की रूपरेखा सम्मेलन में रखी। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद जैसी सामूहिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौती के मुकाबले के लिये एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद दुनिया में शांति, सुरक्षा और विश्वास को कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवाद पर तार्किक प्रहार किए बिना सदस्य देशों में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को बेनकाब करने का प्रयास किया जो आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के बजाय इसको प्रश्रय देने वाले देशों की आलोचना करे, आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम में निष्पक्ष बने। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षामंत्री इस पर भी अड़े रहे कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा एवं भर्त्सना होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई एवं बदनियत ही दिखाई।

चीन लगातार पाक के आतंकवाद पर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाये हुए है। उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना चाहिए लेकिन वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाक के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। चीन आतंक को लेकर जितना संवेदनशील होना चाहिए, पाक के कारण वह

चीन लगातार पाक के आतंकवाद पर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाये हुए है। उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना चाहिए लेकिन वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाक के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा।

उतना नहीं हो पा रहा है। इससे उनकी अन्तर्राष्ट्रीय छवि आहत हो रही है, लेकिन वह सुधरने को तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि एससीओ में चीन-पाक के बीच बढ़ते शरारत भरे तालमेल पर भारत को इस संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सतर्क एवं सावधान होना होगा। भारत को यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संगठन में अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के कारण चीन भारत से संबध सुधारना चाहता है और कुछ मामलों में अपना रुख बदलने के लिए विवश भी हुआ है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत के हितों की अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिम के अन्य देशों की तरह आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए और आतंक के समर्थक पाक का सहयोग एवं समर्थन जारी रखे। भारतीय नजरिये से देखें, तो अमेरिका और चीन, दोनों ही भारत में आतंकवाद के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। भूलना नहीं चाहिए, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक सैन्य जनरल का अपने भवन में भोज के साथ स्वागत किया है। ऐसे घटनाक्रमों से भारत के लिए संदेश साफ है कि वह आंतरिक स्तर पर आतंकियों के लिये अपने संघर्ष को तीखी धार दे। भारत को अपनी आर्थिक एवं सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, तभी आतंकवाद को कुचला जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ उसे अकेले की संघर्षरत रहना होगा।

दरअसल, एससीओ सम्मेलन में भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर भारतीय चिंताओं को जगह दी जाए। इसीलिये सम्मेलन में रक्षामंत्री ने ऑपेरशन सिंदूर की तार्किकता को बताया और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना दुनिया के सामने स्पष्ट थी और दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। इसी से दो देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई, एससीओ सम्मेलन में उस हमले को तवज्जो न देने की रणनीति दरअसल हकीकत के साथ मखौल एवं दौगलापन है। लेकिन सम्मेलन में रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी-7 शिखर सम्मेलन में कही उन बातों को ही विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को कभी पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आश्चर्य जताया था कि आतंक के अपराधियों और इसके पीड़ितों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? यह कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया था।

पाक और उसके करीबी सहयोगियों के नापाक इरादों को दुनिया को बताने तथा भारत की बात हर देश तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहु-पक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे। लेकिन पाक के सदाबहार दोस्त चीन के दबदबे वाले एससीओ सम्मेलन में पाक के आतंकी मनसूंबों को लेकर स्पष्ट नजरिया बनना जरूरी है। एससीओ की घोषणा में अगर यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान की गड़बड़ी में भारत शामिल है, तो फिर भारत को ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। ऐसे झूठे एवं भ्रामक तथ्यों का प्रतिकार जरूरी है। ऐसे झूठ को फैलाकर ही पाक दुनिया से सहानुभूमि जुटाता रहा है। इसलिये किसी भी ऐसे विश्व स्तरीय सम्मेलन में अपनी बात भी पुरजोर ढंग से तथ्यपरक तरीके से रखनी चाहिए। वहां पारित होने वाले प्रस्तावों के प्रति रक्षामंत्री की भांति ज्यादा संवेदनशील एवं सख्त होने की जरूरत है। भारत अपनी इसी नीति को दोहरा कर शत्रु मानसिकता वाले देशों को सबक दे सकेगा। पाक के प्रति भारत की सख्ती हर मोर्चे पर दिखाई दे। भले ही पाक हकीकत न देखने की गलती दोहराता रहे। अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित तथा प्रयोग करने वालों को इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। ऐसा करते हुए वह कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है, वह लगातार गरीबी और कमजोरी का शिकार हो रहा है। आतंकवाद को पोषित करते हुए यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। लेकिन भीख में मिली दया या अनुदान से कब तक खुद को कायम रख पायेगा?

# आतंकवाद में डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग चिन्ताजनक

इंद्रेश शर्मा

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था।

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक नई और गहन चुनौती की ओर संकेत करते हुए आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रयोग को गहन चिन्ताजनक बताया है। रिपोर्ट में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संचालन के बढ़ते खतरे पर न केवल प्रकाश डाला गया है बल्कि गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने आतंकवाद के एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान खींचा है।

इसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी तक आतंकी संगठनों की आसान पहुंच उन्हें और खतरनाक बना रही है। इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नई रणनीति एवं नियंत्रण नीति की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों में पलने-बढ़ने वाले आतंकी संगठन इन तकनीकों का उपयोग कर न केवल फंडिंग जुटा रहे हैं, बल्कि गोपनीयता और पहुँच के नए मार्ग भी तलाश रहे हैं। इसके अलावा, आतंकवादी संगठन अब विकेंद्रीकृत मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसेकि अल-कायदा क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धन जुटाना और संचालन करना। भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान पोषित एवं पल्लवित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए दुनिया से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर चिन्ता जताई और कठोर कार्रवाई की मांग की, इस रिपोर्ट को भारत के रुख का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हुए हमले में पैसों के लेनदेन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया। गोरखपुर वाले केस में आतंकी विचारधारा से प्रभावित शख्स ने इंटरनैशनल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और वीपीएन सर्विस का उपयोग किया था। इस तरह से उसने आईएसआईएल के समर्थन में विदेश में धन भेजा था और उसे भी बाहर से आर्थिक मदद मिली थी। वीपीएन एक डिजिटल तकनीक है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता की लोकेशन और पहचान को छुपाती है। जब कोई व्यक्ति वीपीएन का उपयोग करता है, तो उसका इंटरनेट ट्रैफिक एक एन्क्रिप्टेड सुरंग के माध्यम से किसी अन्य देश के सर्वर से होकर गुजरता है। इससे उसकी वास्तविक पहचान छिप जाती है और वह सेंसरशिप, ट्रैकिंग और जियो-रिस्ट्रिक्शन से बच सकता है।

2024 तक दुनिया में 150 करोड़ से अधिक वीपीएन यूजर्स हैं। इनमें से बड़ी संख्या एशिया और मध्य पूर्व से है, जहां सेंसरशिप या निगरानी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया

और गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला करते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी ऑनलाइन शॉपिंग करती है।

इस साल ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट के 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत इस लिस्ट में फिलहाल सातवें नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस डेटा के बीच अगर कुछ संदिग्ध लोग कुछ हजार डॉलर की खरीददारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर किसी आतंकी हमले में होता है, तो उसे चिह्नित कैसे किया जाए? एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले पहलगाम को लेकर कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला बाहरी आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। उसकी हालिया रिपोर्ट इसी बात को और पुष्ट कर देती है। आतंकियों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है। वे इंटरनेट की दुनिया की ओट ले रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने अब पारंपरिक धन स्रोतों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल वित्तीय माध्यमों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये माध्यम उन्हें सरकार की नजरों से बचाते हुए सीमाओं के पार फंडिंग जुटाने की सहूलियत देते हैं। साथ ही, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर भले हो गया हो, लेकिन उसके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। अनेक ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एफएटीएफ ऑब्जर्वेशन्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को डिजिटल इकोसिस्टम का खुले तौर पर उपयोग करने दिया जा रहा है, या कभी-कभी सरकार की मौन सहमति से। उदाहरण के रूप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल टोकन के जरिए फंड जुटाने की नई तरकीबें अपनाई हैं। कई मामलों में आतंकी फंडिंग के लिए फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक मीडिया अभियानों का सहारा लिया गया है। 'गजवा-ए-हिंद' जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी जमीन से संचालित होकर भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लगे हैं।

भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वारफेयर और साइबर जिहाद की रणनीति पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की नीति का हिस्सा बन चुकी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां डिजिटल माध्यम से न केवल फंडिंग, बल्कि ब्रेनवॉशिंग और भर्ती का कार्य भी तेजी से हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को आतंकी संगठनों की ओर आकर्षित किया जाता है। उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों को डिजिटल भुगतान और चैनलों के माध्यम से सहायता मिलती रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान समेत उन सभी देशों से अपेक्षा की है कि वे डिजिटल वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करें। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। आतंकी संगठनों के ऑनलाइन अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तकनीकी टूल्स विकसित करें। एफएटीएफ का चेतावनी के स्वरों में यह भी कहना है कि यदि आतंक के गढ़ एवं आतंकवाद को पोषित करने वाले इन देशों ने इन सिफारिशों पर अमल नहीं किया तो उन्हें 'हाई रिस्क जॉन' की सूची में डाला जा सकता है। भारत को इस डिजिटल आतंकी खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए-क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रियल-टाइम निगरानी, साइबर आतंकवाद पर विशेष फोर्स का गठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आतंकी कंटेंट की पहचान और हटाने के लिए मजबूत कानून, डार्क वेब और फेक डोनेशन चैनलों की सतत निगरानी आदि कदम उठाने चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने जहां मानव जीवन को सरल और तेज किया है, वहीं इसका दुरुपयोग करके आतंकवाद को नया चेहरा देने की कोशिशें चिंता का विषय हैं। एफएटीएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वे अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद एवं डिजिटल आतंकवाद के अड्डों को समाप्त करें। तभी एक सुरक्षित डिजिटल विश्व और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की कल्पना की जा सकती है। एफएटीएफ रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि आतंकवादियों ने अपने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए वैश्विक दर्शकों से धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म और क्राउडफंडिंग माध्यमों से आतंकवाद के वित्तपोषण प्राप्त किया है। आतंकवादी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल तरीकों से भी धन जुटाकर आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं।

भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट को अपने रुख के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यह रिपोर्ट आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट आतंकवाद के वित्तपोषण और संचालन में शामिल देशों और व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हो सकती है।

# कथावाचक कांड की आड़ में सनातन पर हमला

सपा मुखिया अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त तथा प्रशंसक हैं, वे जहां भी कथा सुनाने जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है।

अनिल वशिष्ठ

इटावा के कथावाचक कांड को राजनीतिक रंग देकर उसमें स्वयं फंसते नजर आ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर ही हमला बोल दिया और उन पर कथा करने के लिए अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाकर नया विवाद उत्पन्न करने का असफल प्रयास किया है। सपा मुखिया जब इटावा की घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में सफल नहीं हुए तब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले धीरेंद्र शास्त्री जी पर बयान देकर सनसनी मचाने का प्रयास किया। वास्तव में अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री जी की आड़ में अपनी पीडीए राजनीति को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं।

सपा मुखिया अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त तथा प्रशंसक हैं, वे जहां भी कथा सुनाने जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। उनके ऊपर सपा मुखिया ने सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत आरोप लगाए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव घोर जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं से बहस करवा रहे हैं कि क्या कथा कहना केवल एक जाति का ही अधिकार है? जब वह इस बहस में पिछड़ गए और फंसने लगे तब बाबा बागेश्वर पर हमलावर हो गये। बाबा बागेश्वर

ने अखिलेश के आरोपों का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? उसमें गरीबों का निःशुल्क उपचार कैसे होगा? बाबा बागेश्वर धाम गरीब कन्याओं का विवाह कैसे संपन्न करवाएगा? बाबा बागेश्वर यदि हनुमानजी का आशीर्वाद लेकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं तो इससे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है ?

ज्ञातव्य है कि बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया पर भी एक सेलेब्रिटी की तरह हैं। उनके फेसबुक पर साढ़े 8 करोड़ सोशल मीडिया एक्स पर दो लाख तथा इंस्टाग्राम पर भी दो लाख से अधिक फालोअर्स हैं जबकि करोड़ों लोग उनके यूटयूब चैनल को नियमित रूप से देखते हैं। अपनी कथा व उपदेशों के माध्यम से वह जनमानस को हिन्दू एकता और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अन्य स्वार्थी नेता उनसे उन पर सामूहिक हमले करते हैं। विगत वर्ष जब बाबा बागेश्वर कथा करने के लिए बिहार गये थे तब वहां के विरोधी दलों के नेताओं ने उनको जेल मे डालने की बात तक कही थी।

बाबा बागेश्वर जी से उन सभी राजनैतिक दलों व नेताओं को समस्या उत्पन्न हो रही है जो जातिवाद व मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम जातिवाद को कैंसर के समकक्ष बताते हैं और हिंदू समाज को एक बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हिन्दू एकता के लिए की गई उनकी पहली पदयात्रा बहुत सफल व लोकप्रिय रही थी, अब वह एक बार फिर नई दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर निकलने वाले हैं।

सच्चाई यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का बाबा पर यह ताजा हमला उनकी हिंदू संत समाज व सनातन विरोधी मानसिकता को ही दशार्ता है। जो लोग अयोध्या, मथुरा व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रबल विरोधी रहे हों, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों का नरसंहार किया हो, जिन्होंने कुम्भ का उपहास किया हो वो एक हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले युवा संत का विरोध ही करेंगे। जब महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मुस्लिम भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था तब सपा मुखिया मौन हो गए थे।

सपा मुखिया ने केवल बाबा पर हमला नहीं किया है अपितु सभी कथावाचकों और संतो सहित सनातन धर्म व उसकी एकता पर किया है। सपा मुखिया को स्पष्ट रूप से रामायण, महाभारत, भागवत कथा, आरती, मंदिर, गौशालाओं, गीता आदि सभी से नफरत है। सपा मुखिया को हर उस अच्छी चीज से नफरत है जिससे हिन्दू समाज का गौरव बढ़ता है। सपा के लोग प्रायः रामचरित मानस आदि ग्रंथों का अपमान करने से नहीं चूकते कभी फाड़ते हैं कभी जलाते हैं। है। सपा मुखिया गौशालाओं से बदबू आती है जैसी बातें कहकर भगवान श्रीकष्ण व समस्त यदुवंशी समाज का अपमान कर चुके हैं।

सपा मुखिया ने पहले कथावाचक घटना को राजनैतिक रंग देकर फिर बाबा बागेश्वर पर हमला करके एक बहुत ही निम्न राजनैतिक चाल चली है। उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं वरन पूरे देश को यह समझना होगा। यह समय जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर स्वार्थी राजनेताओं को पूरी तरह से घूल चटाने का समय आ गया है ।

एन के शर्मा

# न्यायालय में निर्णायक मोड़ लेता श्रीकृष्ण जन्मभूमि मसला

**श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के साथ दस बिंदुओं पर बिना किसी अधिकार के समझौता किया था। 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है।**

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित संरचना' घोषित करने की हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालती रिकॉर्ड और आगे की सभी कार्यवाहियों में मस्जिद को आधिकारिक रूप से विवादित स्थल के रूप में दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने मौखिक रूप से याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में हिंदू पक्ष द्वारा दायर आवेदन को ह्लइस चरण मेंह्व खारिज किया जा रहा है। इस फैसले को लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्षकार भले ही राहतकारी माने, लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह भूमि विवाद पर जो भी फैसला अंतिम रूप से आएगा, वह बहुत प्रभावी होगा, न्यायसंगत होगा। अतः ऐसे किसी पुख्ता फैसले तक पहुंचते हुए पूरी सावधानी एवं धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। इस फैसले से इस विवाद में एक नया रुख सामने आया है, जो महत्वपूर्ण और विचारणीय है।

याचिका में यह मांग की 'शाही ईदगाह मस्जिद' शब्द की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द का इस्तेमाल किया जाए, अगर यह शाब्दिक बदलाव किया जाता, तो एक तरह से यह इस विवाद पर निर्णायक फैसले जैसा होता। जिससे अनावश्यक विवाद या अड़चन की संभावनाएं पनपती। यह विवाद राजनीति मोड़ भी ले सकता था, निश्चित ही अगर राजनीति होगी, तो अंतिम फैसले में अनावश्यक रूप से समय लगेगा। साथ ही, अशांति की आशंका भी बढ़ेगी। इसलिये अदालत के फैसले को सकारात्मक नजरिये से देखा जाना चाहिए। नए नामकरण की यह कोशिश उच्च न्यायालय में अगर नाकाम हुई है, तो कोई अचरज नहीं, ना ही किसी पक्ष की जीत और किसी पक्ष की

हार है। इतने संवेदनशील मसले में यह नामकरण पूरे मुकदमे को प्रभावित करता, अतः अदालत ने समझदारीपूर्ण सही फैसला किया है। 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि' का स्थान न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमिट प्रतीक भी है। परंतु, इसी पवित्र स्थल पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के साथ एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है जो अब न्यायालय की चौखट पर निर्णायक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है।

जन्मभूमि पक्ष के याचिकाकताओं का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित है, अतः जन्मभूमि पक्ष को भूमि पर कब्जा दिया जाए। मस्जिद के ढांचे को हटाया जाए, मूल मंदिर का निर्माण हो, वहां मुस्लिम मजहबी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इन्हीं मांगों के साथ जन्मभूमि पक्ष की ओर से करीब 18 मुकदमे दायर हैं। इनकी सुनवाई यथावत जारी रहेगी। नामकरण संबंधी आवेदन के खारिज होने का कोई असर मूल मुकदमों पर नहीं पड़ेगा। अब दोनों ही पक्षों को पूरे संयम का परिचय देना चाहिए। अदालत का ताजा रुख न किसी के लिए बड़ी हार है और न किसी के लिए बड़ी जीत। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मभूमि के पक्ष में दायर याचिकाओं को अदालत ने सुनने लायक माना है। पहले इन याचिकाओं को ईदगाह पक्ष ने चुनौती दी थी, पर अदालत ने चुनौतियों को खारिज कर दिया था। पिछले वर्ष 1 अगस्त को उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अन्य कानूनों के आधार पर ईदगाह पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए जन्मभूमि पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। अब जब सुनवाई आगे बढ़ गई है, तब ऐसी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुस्लिम कब्जे से मुक्त हो और वहां मन्दिर के निर्माण का स्वप्न आकार ले।

हिंदू याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक और रूपांकन अभी भी दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि केवल अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने से स्वामित्व स्थापित नहीं होता है और उन्होंने अयोध्या विवाद के साथ समानताएं बताईं। अब जब नामकरण या नाम परिवर्तन की कोशिशों पर अदालत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तब जन्मभूमि पक्ष को छोटे-छोटे फैसले कराने की कोशिश करने के बजाय बड़े फैसले तक पहुंचने की तैयारी एवं जल्दी दिखानी चाहिए, यह विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए, उतना अच्छा है। श्रीराम मन्दिर-अयोध्या की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर वहां भव्य मन्दिर निर्माण की ओर सारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। देर भले ही लगे लेकिन अदालत का फैसला श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में आना है, क्योंकि इस विवाद में जन्मभूमि पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज या सुबूत मौजूद हैं, जिनका अदालत में परीक्षण होना है। निस्संदेह, पूरे परीक्षण और विचार के बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन इस फैसले की दिशाएं मथुरा को पुराणों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के रूप में वर्णित उद्धरणों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त करके वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार, यह मस्जिद मंदिर को ध्वस्त करने उसके अवशेषों पर ही बनाई गई थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के साथ दस बिंदुओं पर बिना किसी अधिकार के समझौता किया था। 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। जब भूमि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम पर थी ही नहीं तो उसके द्वारा समझौता कैसे किया जा सकता है? 2020 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति याचिका के माध्यम से फिर से यह मुद्दा न्यायालय में आया। याचिका में यह दावा किया गया कि 13.37 एकड़ भूमि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है और वहां मौजूद ईदगाह मस्जिद अवैध है। साथ ही, 1951 का समझौता भी अवैध, असंवैधानिक और शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई। 2023 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मथुरा की जिला अदालतों ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि की वैज्ञानिक जांच की अनुमति दी, जैसा श्रीरामजन्मभूमि मामले में हुआ था। अदालत ने 1951 के समझौते की वैधता पर सवाल उठाए हैं क्योंकि कटरा केशवदेव ट्रस्ट को जन्मभूमि का संप्रभु प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता था।

जन्मभूमि पक्ष की याचिकाओं को प्रारंभिक दौर में ही खारिज करने से इनकार किया गया और मुकदमे की सुनवाई की अनुमति दी गई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था एवं ऐतिहासिकता है कि वर्तमान ईदगाह मस्जिद के नीचे श्रीकृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मंदिर के अवशेषों की पुष्टि करते हैं। औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनवाने का स्पष्ट उल्लेख फारसी शिलालेखों व इतिहासकारों की रचनाओं में भी मिलता है। पूजा स्थल अधिनियम-1991 का कानून 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बनाए रखने की बात करता है, परंतु श्रीकृष्ण जन्मभूमि एक जीवित और सतत पूजा स्थल है, और इसमें अपवाद की आवश्यकता है जैसा अयोध्या मामले में देखा गया। यह विवाद केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक न्याय की मांग भी है। यह मसला न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा इसलिये भी करता है कि यह अधिसंख्य जनभावनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अब केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि न्याय और आस्था के संतुलन की कसौटी बन चुका है। जैसे अयोध्या में शताब्दियों के संघर्ष के बाद न्याय की विजय हुई, वैसे ही मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी न्याय की प्रतीक्षा है। न्यायालय का नया दृष्टिकोण एक आशा की किरण बनकर उभरा है, जो भविष्य में ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

जन्मभूमि पक्ष के याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित है, अतः जन्मभूमि पक्ष को भूमि पर कब्जा दिया जाए। मस्जिद के ढांचे को हटाया जाए, मूल मंदिर का निर्माण हो, वहां मुस्लिम मजहबी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इन्हीं मांगों के साथ जन्मभूमि पक्ष की ओर से करीब 18 मुकदमे दायर हैं। इनकी सुनवाई यथावत जारी रहेगी।

कपिल चौहान

# जाम के झाम से मुक्ति के हों पुख्ता इंतजाम

**27** जून को इंदौर-देवास हाईवे पर करीब पर 40 घंटे तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें 4000 से ज्यादा वाहन फंस गए थे। इस दौरान 3 लोगों की जान चली गई। 14 जून को केरल के कन्नूर में कोट्टियूर के पास एक तीन वर्षीय बच्चे की अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस के भीषण ट्रैफिक जाम में फंस जाने से मौत हो गई।

7 जून दिल्ली से आए एक 62 वर्षीय पर्यटक कमल किशोर टंडन की मसूरी में भीषण ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। 6 मई उप्र के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और राजमार्ग पर तीन घंटे तक जाम फंसे रहने की वजह से उसे वक्त पर उचित उपचार नहीं मिला और इस वजह से उसकी मौत हो गई।

24 अप्रैल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मुख्य बाजार देहरा में समय सड़क निर्माण कार्य के कारण लगे भारी जाम ने 75 साल के बुजुर्ग की ज़िंदगी छीन ली। 24 फरवरी कोटा राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दरा नाल में लगने वाले भीषण जाम ने एक मासूम की जान ले ली। ये तो बानगी भर है। इस तरह की खबरें अक्सर सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। दो चार दिन के हो हल्ले के बाद गाड़ी पुराने ढर्रे पर दौड़ने लगती है।

ताजा प्रकरण इंदौर-देवास हाईवे पर 40 घंटे के जाम का है। 40 घंटे का जाम था...कोई सोच भी नहीं सकता कि आजादी के 75 साल बाद, 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 40 घंटे लग सकते हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने में आमतौर पर 16 से 20 घंटे लगते हैं। मतलब जितने में दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट का आना जाना हो जाए, उतने में इंदौर से देवास नहीं पहुंच सके। इंदौर से देवास तक का रास्ता महज 40 किलोमीटर है।

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। निश्चित रूप से इस दुर्घटना और हजारों लोगों के घंटों जाम में फंसे रहने के मामले में जहां एनएचएआई की तरफ से माफी मांगने की जरूरत थी, वहीं उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये दोष लोगों पर लगाते हुए असंवेदनशील बयान दे डाला। 30 जून को अदालत में जवाब देते हुए एनएचएआई के वकील ने कहा कि ह्लोग बिना जरूरी काम के इतनी सुबह घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं ?ह्व एनएचएआई की इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया।

उनके इस बयान को सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनएचएआई घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और घटना के लिए आम लोगों

को ही दोषी बताने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई के रुख को कठोर और संवेदनहीन बताया है, जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला है। विवाद बढ़ने पर एनएचएआई ने कहा कि,यह टिप्पणी अथॉरिटी के आधिकारिक विचारों को नहीं दशार्ती।

देश में जहां एक तरफ ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए सड़कों, हाई-वेज और एक्सप्रेस-वेज को बनाने का काम जोरों-शोरों पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे शहर भी हैं, जो अंदरूनी ट्रैफिक से काफी ज्यादा परेशान हैं। असल में, ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे शहर भी जूझते हैं। लेकिन बड़े शहरों में यह एक संकट का रूप लेने लगा है।

एक जानकारी के मुताबिक एक घंटे जाम में एक लीटर ईंधन बर्बाद होता है। जितनी ईंधन की खपत होगी, उतना ही ज्यादा सीओटू उत्सर्जन भी होगा, जो पर्यावरण और प्रदूषण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक अनुमान के अनुसार, महानगरों में और हाईवे पर देश में हर साल लगने वाले ट्रैफिक जाम से हर साल तकरीबन 1.4 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा है।

टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अनुसार, देश में कोलकाता का ट्रैफिक सबसे धीमा है। बेंगलुरु ने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। कमोबेश ऐसे हालात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, चंडीगढ़, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, अमृतसर, अहमदाबाद, वाराणसी और देश के अन्य महानगरों और शहरों के हैं।

डाक्टरों के अनुसार, जाम में फंसने वालों को अकसर ब्लड प्रेशर बढ़ने, बर्नआउट, सांस की बीमारी, डिहाईड्रेशन, फीवर, घबराहट, सीने में दर्द आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंभीर मरीज लंबे समय तक जाम में फंस जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि अब जाम में एंबुलेंस फंसी तो इसे अपराध माना जाएगा और मरीज को नुकसान पहुंचाने के तहत कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके स्थिति में कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता।

इसमें दो राय नहीं कि सड़कों के नेटवर्क सुधार से उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत हुई है तो उद्योग-व्यापार को भी गति मिली है। लेकिन

इससे जुड़ी तमाम विसंगतियां भी सामने आई हैं। सड़कों के त्रुटिपूर्ण डिजाइन व निर्माण में चूक को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वहीं अकसर बड़ी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अंतहीन असुविधा भारतीय यात्रियों के लिए रोजमर्रा के अनुभव हैं। अधिकांश साइटों पर निर्माण से जुड़ी, यात्रियों के अनुकूल सर्वोच्च परंपराओं को अपनाना और यातायात में व्यवधान को कम से कम करना सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

जानकारों के मुताबिक, जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा लोगों को कार पूलिंग के लिए जागरूक करना होगा जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या को कम किया जा सके। सड़क पर जाम का एक बड़ा कारण जगह-जगह कट का होना भी है। पैदल और छोटे वाहनों के आवागमन के लिए मुख्य सड़कों के साथ सर्विस रोड बनाए जाने से भी जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जिन स्थानों पर घनी आबादी के चलते सर्विस रोड नहीं बनाए जा सकते। वहां एलिवेटेड रोड, अंडरपास और फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया जा सकता है।

जाम से जूझते शहरों में सड़कों की भीड़भाड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार सरकार ने राज्यों की राजधानियों समेत दस लाख से अधिक आबादी वाले 94 शहरों में जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिंग रोड, बाईपास समेत अन्य उपाय करने की योजना बनाई है। यूपी में लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलों, रिंग रोड और बाईपास का जाल बिछाया जाएगा। इनके निर्माण पर लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 6124 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगा। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की ओर से यह खाका खींचा गया है।

निस्संदेह, देश के शहरों में आए दिन जाम लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शासन-प्रशासन को इसके तार्किक समाधान की दिशा में वैज्ञानिक तरीके से गंभीरता के साथ प्रयास करने चाहिए। जाम की सूचना मिलने पर उसे खुलवाने की तत्काल पहल होनी चाहिए। यात्रियों के लिये तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। निश्चय ही, इंदौर-देवास हाईवे की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शासन-प्रशासन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई को गंभीरता से लेना चाहिए। उन तमाम आशंकाओं को टालना चाहिए जो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति के कारक बन सकते हैं।

# भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना

वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करक वापस चली आएगी।

राजेंद्र सिंह

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर, स्वदेशी तकनीक से समृद्ध, सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय सेना को भविष्य की रक्षा चुनौतियों लिए इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि भूमि से लेकर वायु और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाईयों तक अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। आज अति आधुनिक ड्रोन से लेकर अविश्वसनीय मारक क्षमता वाली मिसाइलों तक का निर्माण भारत में किया जा रहा है। विगत दिनों ईरान-इजराइल के मध्य संघर्ष के बीच ईरान के शक्तिशाली व मजबूत परमाणु संयंत्रो को नष्ट करने की क्षमता न होने के कारण इजराइल को भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ा था। ऐसी ही परिस्थतियों से बचने के लिए भारत अब बंकर ब्लस्टर बम बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करक वापस चली आएगी।

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं संगठन अग्नि 5 मिसाइल के दो नये एडवांस प्रारूप विकसित कर रहा है जिसमें प्रथम प्रारूप बंकर ब्लस्टर वॉरहेड या विस्फोटक ले जाने वाला होगा जो जमीन के भीतर 80 से 100 मीटर तक जाकर दुश्मन के

ठिकानों को ध्वस्त करेगा जबकि दूसरा प्रारूप विस्फोटक ले जाने वाला होगा। ये दोनों ही प्रारूप दुश्मन के डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो को ध्वस्त करके वापस लौट आएंगे। अग्नि -5 बंकर ब्लस्टर मिसाइल जमीन, सड़क और मोबाइल लांचर से दागी जाएगी। अग्नि-5 भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज 5 से 7 हजार किमी तक हैं ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। भारत का बंकर ब्लस्टर बम अमेरिकी बम से भी अधिक क्षमतावान बनाया जा रहा है।भारत की बंकर ब्लस्टर मिसाइल अमेरिकी बम से अधिक गहराई तक निशाना लगा सकती है। भारत को चीन और पाकिस्तान से पैदा हुए खतरे को देखते हुए ही इस प्रकार की मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय नौसेना को मिला तमाल- इसी प्रकार ब्रहमोस मिसाइलों से लैस अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है जिसके कारण अब समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ गई है।इस बहुददेशीय अतिआधुनिक युद्धपोत का जलावतरण रूस के केलिनिनग्राद में हुआ। नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल यह युद्धपोत हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तान से लगती सीमा पर निगरानी में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जायेगा। तमाल युद्धपोत विगत दो दशकों में रूस से प्राप्त क्रियाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला में आठवां युद्धपोत है। यह पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में अधिक उन्नत है।इसमें लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उन्नत 100 मिलीमी की तोप, मानक 30 मिलीमीटर गन क्लोज -इन हथियार प्रणाली के अलावा आधुनिक समय की प्रणाली अत्यधिक भार वाले टारपीडो तत्काल हमला करने वाले पनडुब्बी रोधी, रॉकेट और अनेक निगरानी एवं अग्नि नियंत्रण रडार तथा अन्य प्रणालियां शामिल हैं।युद्धपोत का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है। इसकी मारक क्षमता भी उसी तरह तेज, आक्रामक और निर्णायक है।इसका शुभंकर भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर भालू जाम्बवंत और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू की समानता से प्रेरित है। तमाल युद्धपोत का निर्माण रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में हुआ है और इसमें 26 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में बना है अब ऐसा कोई भी युद्धपोत भारत में ही बनेगा जिसके बाद भारत की नौसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत के कुशल संचालन व रखरखाव के लिए 250 नौसेना कर्मियों ने रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बहु मिशन युद्धपोत भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। भारत की नोसेना को एक और स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरि का उपहार भी मिला है।इस युद्धपोत में सुपरसोनिक सतह से सतह से मार करने वाली प्रणाली लगी है। इसमें 76 मिमी गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी की रैपिड फायर गन सहित डीजल इंजन और गैस टर्बाइन युक्त सीओडीजी प्रणाली है।इस 3900 टन वजनी और 125 मीटर लंबे युद्धपोत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। यह देनों ही युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं।

# अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने किए 7 परीक्षण

## गगनयान मिशन में कैसे आएंगे काम

**संजय बैंसला**

शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारी अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है।' भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लौट आए हैं। वे 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। मंगलवार, दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा पर करीब 550 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। शुभांशु का अंतरिक्ष अनुभव भारत के गगनयान मिशन में मदद करेगा। शुभांशु शुक्ला ने कहा, 'मैं इस मिशन के जरिए देश के बच्चों को प्रेरित करना चाहता हूं। अगर मैं एक बच्चे को भी प्रेरित कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैं सफल रहा।' अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए और यकीन मानिए वो अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं और इसको लेकर देश में खास उत्साह दिखा। उनके मिशन को लेकर बच्चों में जिज्ञासा थी। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से धरती पर लौटने पर सारे हिंदुस्तान की निगाह लगी हुई थी। जैसे ही ये तस्वीर आई, देश ने राहत की सांस लेने के साथ गर्व भी महसूस किया।

### धरती पर लौटने के बाद शुभांशु की खुशी...

धरती पर लौटने पर शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर गर्व और होठों पर मुस्कुराहट दिखी। कैप्सूल से बाहर निकलते ही शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। करीब 23 घंटे के सफर के बाद भारतीय समय के मुताबिक, दोपहर 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैशडाउन कहते हैं। पैराशूट की मदद से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर उतरा। पृथ्वी पर वापसी के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पानी से निकाला गया। शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन धरती की ओर 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। जब यह बहुत करीब आया तो स्पीड कम कर दी गई। कैप्सूल की बाहरी सतह पर हीट शील्ड 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर रही थी। शुभांशु ने 1 करोड़ 39 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है।

### स्पेस स्टेशन से लौटने की पूरी प्रक्रिया...

शुभांशु शुक्ला सहित चारों अंतरिक्ष यात्री एक दिन पहले शाम 4.45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन

से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। ये सभी 26 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजकर 1 मिनट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की इस कामयाबी में इसरो ने भी अहम भूमिका निभाई। इसरो ने इस मिशन के लिए करीब 550 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

### प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं

शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारी अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है।'

### भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला

शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले साल 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और वो वहां 8 दिन तक रहे थे। अब जबकि शुभांशु अंतरिक्ष में कई तरह के प्रयोग करने के बाद धरती पर लौट आए हैं, तो देश के कई वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे भारत के सपनों को आकार देने में मदद मिलेगी।

### वैज्ञानिकों की राय और उम्मीद...

विलियम सेल्वमूर्ति (पूर्व डीजी DRDO) और खगोल वैज्ञानिक अमिताभ ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के मिशन का भविष्य में फायदा मिलेगा। शुभांशु को भारत आने में अभी वक्त लगेगा और हर किसी को उनके आने का इंतजार है।

### लखनऊ के स्कूल में खुशी का माहौल

लखनऊ के जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की थी, उसी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उनके परिवार के साथ स्कूली बच्चों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा। जैसे ही शुभांशु की सफल लैंडिंग हुई, लोग खुशी से झूम उठे। शुभांशु के माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।

दिल्ली के CSIR-NPL ऑडिटोरियम में भी शुभांशु की रिटर्न जर्नी का सीधा प्रसारण दिखाया गया। भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का ये अंतरिक्ष मिशन केवल रिकॉर्ड बनाने का मौका नहीं था। ये भविष्य की तैयारी थी। ये मिशन भारत के खुद के दम पर अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के सपने का आधार बनेगा। यहीं से भारत के गगनयान मिशन का रास्ता निकलेगा।

### दो ऐतिहासिक रिकॉर्ड...

शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन पर दो रिकॉर्ड बनाए। पहला, वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। दूसरा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी यह यात्रा राकेश शर्मा द्वारा 1984 में उड़ान भरने के 41 साल बाद हुई।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने में मदद के लिए 7 खास परीक्षण किए। इनमें मांसपेशियों के नुकसान को डिकोड करने, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने और अंतरिक्ष में हरे चने और मेथी के बीज को अंकुरित करने के प्रयोग शामिल थे।

### Axiom-4 मिशन से मिले अनुभव

Axiom-4 मिशन अपने साथ कई डेटा और अनुभव लेकर लौटा है कि अगर इंसान को स्पेस में लंबा वक्त रहना है तो वहां खाने-पीने का क्या इंतजाम हो सकता है। इस मिशन से स्पेस साइंटिस्ट को स्पेस में इंसान के दिमाग के ब्लड सकुर्लेशन को समझने का नजरिया भी मिला।

### मेडिकल जांच और रिहैबिलिटेशन

शुभांशु भले ही धरती पर लौट चुके हों, लेकिन उनकी चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। शुभांशु शुक्ला अगले सात दिनों तक रिहैबिलिटेशन में रहेंगे और शरीर को धरती के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। इस दौरान मेडिकल टीम उनकी सेहत का ध्यान रखेगी।

शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं है। ये भारत की आकांक्षाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आत्मविश्वास की कहानी है, जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

**अंतरिक्ष से लौटे भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से बधाई दी और उनकी उपलब्धि को उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण बताया।**

# क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक?

**महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में 'जीविका' स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई 'जीविका' ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है।**

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो?

यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है।

उज्जवल रस्तौगी

लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निदेशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव 'महिला संवाद' कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों,

माताओं और बहनों की आवाज को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है।

यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निमार्ताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं।

महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर जोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरूआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में 'जीविका' स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई 'जीविका' ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया 'जीविका दीदी' नाम आज एक पहचान बन चुका है।

वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। महिला संवादः भविष्य के विकास का रोडमैप

'महिला संवाद' कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्त्वपूर्ण और व्यवहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दशार्ती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और 'जीविका दीदी की रसोई' व 'जीविका दीदी हाट' जैसी पहल शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर राइस मिलों की स्थापना, वेजिटेबल मार्ट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की मांगें भी मुखरता से उठी हैं।

बुनियादी सुविधाओं के लिए 'जीविका भवन', लाइब्रेरी और पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की मांग की गई है। सामाजिक सुधारों में शराबबंदी की तर्ज पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, और सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी, हेल्प डेस्क तथा प्रखंड स्तर पर महिला थाना बनाने की मांगें भी प्रमुखता से रखी गई हैं।

यह आशा की जाती है कि सरकार इन मांगों पर शीघ्रता से विचार कर अपेक्षित निर्णय लेगी। यह संतोषजनक है कि बिहार सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है। 2005 से पूर्व और उसके बाद बिहार में आए इस सकारात्मक बदलाव को आज हर स्तर पर देखा और महसूस किया जा रहा है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैंः 93.11% महिलाएं आज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, 91.73% घरों में घरेलू हिंसा कम हुई है, और 87.75% महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत मानती हैं।

आज बिहार में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लगन और मेहनत से अपना मुकाम बना रही हैं। यह बदलता बिहार है, जहाँ की बेटियां अब सिर्फ घर की चौखट के भीतर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और नीति-निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

विकसित बिहार के निर्माण में

# प्रकृति का विक्षोभ या विकास की विफलता ?

हरेन्द्र शर्मा

**हिमालय को केवल भूगोल नहीं, अध्यात्म का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और घाटियां धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती हैं। जब इन स्थानों पर अंधाधुंध निर्माण होता है, तो केवल भू-आकृति नहीं, सांस्कृतिक चेतना भी नष्ट होती है।**

बीते कुछ वर्षों में पहाड़ों में बारिश एवं बादल फटना अब डर, कहर और तबाही का पर्याय बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों में हर वर्ष मानसून के साथ भयावह भूस्खलन, बादल फटना, पुल बहना और सड़कें टूटना एक आम दृश्य बन गया है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता, सरकारी निर्माण की लापरवाही और अनियोजित विकास की पोल खोलने वाला यथार्थ है।

निश्चय ही हाल के वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है और बारिश की तीव्रता बढ़ी है। हर वर्ष जब मानसून की पहली बारिश पहाड़ों को भिगोती है, तो स्थानीय जनजीवन एक नई उम्मीद के साथ खिल उठता है। खेतों में हरियाली, नदियों में जल, और प्रकृति की शीतलता-मानसून एक उत्सव जैसा लगता है। लेकिन हालिया मानसूनी बारिश और मौसमी विक्षोभ की जुगलबंदी से हिमाचल के कई इलाकों में तबाही का जो भयावह मंजर उभरा, उसे हमें कुदरत के सबक के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत व लापता होने के साथ ही अरबों रुपये की निजी व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है।

2023 और 2024 के मानसून ने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो कहर बरपाया, वह केवल आँकड़ों में सीमित नहीं है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए, हजारों लोग बेघर हुए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कों, सुरंगों और इमारतों के निर्माण ने जिस तरह से पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की, वह अब प्रकृति के प्रतिशोध का कारण बन रही है। उत्तराखंड में 'ऑल वेदर रोड', हिमाचल में सुरंगें और जल विद्युत परियोजनाएं-इन सभी ने विकास के नाम पर जिस प्रकार अंधाधुंध खुदाई और कटान किए हैं, उससे पर्वतीय क्षेत्र अपनी स्थायित्व खोते जा रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद कई निर्माण कार्यों में भूगर्भीय सर्वेक्षण की अनदेखी की गई। नतीजा यह हुआ कि हल्की-सी भारी बारिश में ही सड़कें धंस जाती हैं, इमारतें दरकने लगती हैं, और पूरा गाँव मलबे में दब जाता है। वास्तव, पहाड़ी इलाकों में अतिवृष्टि से आपदा का जो भयावह मंजर उभर रहा है, उसके मूल में सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारक नहीं है। दरअसल, इस तबाही के मूल में हमारी नाजुक हिमालयी पारिस्थिकीय तंत्र के प्रति बड़ी लापरवाही भी है। इस तथाकथित विकास के नाम पर हमने उन सीढ़ीनुमा रास्तों को दरकिनार कर दिया, जो पहाड़ों को मजबूती देते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी तीव्रता और आवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसकी मुख्य वजहें हैं-अनियंत्रित पहाडों की कटिंग और खुदाई, बढ़ता भारी वाहन यातायात, जल निकासी की अव्यवस्था

एवं वन क्षेत्र का अत्याधिक क्षरण। सरकारी निर्माण एजेंसियां अक्सर तय मानकों की अनदेखी करती हैं। निर्माण सामग्री घटिया होती है और मुनाफाखोरी के चक्कर में दीवारें और पुल बरसात में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और पर्यावरण वैज्ञानिक लगातार चेताते रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं। फिर भी, निर्माण कार्यों के लिए भू-सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और जनसुनवाई की प्रक्रियाओं को या तो टाल दिया जाता है या खानापूर्ति भर की जाती है। चार धाम यात्रा मार्ग पर बनने वाली सड़क परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रोका और सुझाव दिए कि पहाड़ों को काटने की बजाय टनल या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। निश्चय ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मौसम के बिगड़े तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जल-प्रलय सी आपदा का विनाश निश्चय ही भयावह है। वैज्ञानिकों को इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। इस साल की मानसूनी बारिश में मंडी जिले में बादल फटने की घटनाओं ने बुनियादी ढांचे, घरों, सड़कों और बगीचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसने पहाड़ों में विकास के स्वरूप को लेकर फिर नये सिरे से बहस छेड़ दी है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण राजमार्ग भूस्खलन और अतिवृष्टि से बाधित रहे हैं। कांगड़ा घाटी में ऐतिहासिक रेल परिवहन को स्थगित करना पड़ा है।

शिमला के पास एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भयभीत किया। जब बारिश आती है, तो केवल इमारतें और सड़कें नहीं ढहतीं, आम लोगों का जीवन भी उजड़ जाता है। लोग रातोंरात बेघर हो जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली-पानी की सुविधाएं बंद हो जाती हैं। प्रशासनिक अमला अकसर घटनास्थल पर देर से पहुँचता है और राहत कार्यों में राजनीतिक रस्साकशी आड़े आ जाती है।

राहत कैंपों में भोजन, शौचालय और दवाइयों की भारी कमी रहती है। जब किसी राज्य में बड़ी आपदा आती है, तभी मीडिया और नेताओं की नजर जाती है। हेलिकॉप्टर से निरीक्षण, मुआवजे की घोषणाएं, और 'हम साथ हैं' जैसे बयान आते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होता है, पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। लंबे समय तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य अधर में लटकते हैं।

निश्चय ही मौसम के मिजाज में तल्खी नजर आ रही है लेकिन इस संकट के मूल में कहीं न कहीं अवैज्ञानिक विकास, खराब आपदा प्रबंधन और निर्माण में पारिस्थितिकीय ज्ञान की उपेक्षा भी निहित है। जिसने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। दरअसल, पानी के प्रवाह के जो प्राकृतिक रास्ते थे, हमने उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं। हमने अपेक्षाकृत नयी हिमालयी पर्वतमालाओं पर इतना भारी-भरकम विकास व निर्माण लाद दिया कि वे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं।

निर्माण कार्य में स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला और प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग बढ़ाया जाए। भू-सर्वेक्षण और ईआईए को अनिवार्य किया जाए, हर निर्माण से पहले वैज्ञानिक स्तर पर जमीन की जाँच और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हो। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए और जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए। गाँवों और कस्बों के स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि निर्माण कार्य जमीनी जरूरतों और जोखिमों के अनुसार हो।

हिमालय को केवल भूगोल नहीं, अध्यात्म का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और घाटियां धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती हैं। जब इन स्थानों पर अंधाधुंध निर्माण होता है, तो केवल भू-आकृति नहीं, सांस्कृतिक चेतना भी नष्ट होती है। पर्वतीय जीवन में तबाही के पीछे केवल प्रकृति नहीं, हमारी नीति, नियत और विकास का वह मॉडल जिम्मेदार है जो केवल तात्कालिक लाभ और मुनाफे पर केंद्रित है। हम पहाड़ों को केवल पर्यटक स्थल या परियोजना-स्थल की दृष्टि से न देखें, बल्कि वहां के पर्यावरण, संस्कृति और जीवन पद्धति को समझें और संरक्षण का दायित्व लें। नहीं तो हर बारिश के साथ पहाड़ों से जीवन खिसकता जाएगा और एक दिन यह संकट केवल स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय बन जाएगा।

दरअसल, पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए नये सिरे से निर्माण के मानक तय करने होंगे। वहीं दैनिक जल निकासी और बरसाती पानी के प्रवाह के लिये वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करनी होगी। निश्चित रूप से पहाड़ों में लगातार बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे में पहाड़ की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने की कीमत हम चुका रहे हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के लिये अतीत के सबक सीखकर हमें विकास के नये मानक तय करने होंगे।

ऐसा लगता है कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं कि यदि बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसा हादसा मंडी अथवा शिमला में हुआ, वैसे हादसें होते ही रहेंगे और उनका दोष प्रकृति पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाएगी। बात केवल हिमाचल की ही नहीं है, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से तीर्थयात्री संकट में पड़े हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि हम बार-बार विकसित भारत की बात करें, लेकिन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी करें और मानक होते हुए भी उनका पालन न करें। इस तरह से तो हम विकसित देश नहीं बन सकते।

# कांवड़ यात्रा
# आस्था का संगम

## शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो कांवड़ यात्राः सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न होनी चाहिए। इसके लिए शासन-प्रशासन पूरी सजगता, संवेदनशीलता और सक्रियता से कार्य करे। यात्रा में विघ्न डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

# महिलाओं की सुरक्षा पर रखें विशेष निगरानी संवेदनशील इलाकों में CCTV से हो निगरानी

ललित कुमार

योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, चिकित्सा, पेयजल, भोजनालय, विश्रामालय और शौचालयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के जुटने के दृष्टिगत महिला पुलिस बल की प्रभावी तैनाती हो। संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जाए। खुफिया तंत्र पूरी सक्रियता से कार्य करे, ताकि घुसपैठ या अराजकता की किसी भी कोशिश को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान श्रद्धा, मयार्दा और अनुशासन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि वह पवित्र नदियों से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। प्रशासन से पूर्ण सहयोग बनाए रखें।

## शिव भजन का करें प्रसारण

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जरूरी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए और शिव भजनों का प्रसारण सुनिश्चित हो, जिससे श्रद्धालु भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करें। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रमुख अवसरों पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की व्यवस्था की जाए। सभी प्रमुख स्थलों पर चिकित्सा शिविर, प्राथमिक उपचार केंद्र और एंबुलेंस सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि खानपान की सामग्री की गुणवत्ता और शुद्धता की नियमित जांच सुनिश्चित करें।

## किसानों को खाद की न हो कमी कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं : योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद की तस्करी और कालाबाजारी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को खाद की कमी न होने पाए। इसके लिए खाद वितरण की समीक्षा हो और जिलाधिकारी स्तर से इसकी निगरानी हो।

सीएम ने कहा कि खाद की कमी पर तुरंत वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। उन्होंने थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की नियमित

जांच के निर्देश के साथ गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने और केस दर्ज कराने को कहा। कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ समन्वय बनाकर शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान के कार्य करने का निर्देश दिया। रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खुफिया तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ या उपद्रव की आशंका को समय रहते रोका जा सके।

## श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, पेयजल, भोजनालय, चिकित्सा, शौचालय और विश्रामालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की जाए।

## आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी

उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख स्थलों पर चिकित्सा शिविर, प्राथमिक उपचार केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहें। अंत में सीएम योगी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे श्रद्धा, मयार्दा और अनुशासन के साथ यात्रा करें।

## अफवाहों पर नियंत्रण और सोशल मीडिया निगरानी

इस बार यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों पर अफवाहों से बचाव के लिए एक विशेष सोशल मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया है, जो 24 घंटे ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखेगा। झूठी या भड़काऊ खबरों को फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने आम जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग की अपील की है।

# 11 जोन, 24x7 कंट्रोल रूम...

# सीएम योगी का खास प्लान

सावन में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने इस बार कई विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए 11 जोन में विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनकी 24x7 निगरानी महिला अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही, हेल्पलाइन नंबरों पर भी महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेंगी ताकि किसी भी असुविधा की स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।

पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 66000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती में से करीब 15 प्रतिशत बल महिला पुलिसकर्मियों का है, जिसमें 8,541 महिला सिपाही और 1,486 महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं. हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बार यात्रा में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. इनमें 60 से 70 लाख महिलाएं शामिल हो सकती हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला केंद्रित सुरक्षा मॉडल अपनाने के निर्देश दिए थे. सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष हेल्प डेस्क, क्यूआरटी गश्त, और रात्रिकालीन ड्यूटी में महिला बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

## हेल्प डेस्क पर रहेंगी महिला कांस्टेबल

जानकारी के मुताबिक यात्रा मार्गों पर 150 से अधिक महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन सभी पर महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है, जो न केवल सहायता करेंगी बल्कि संवेदनशील मामलों में परामर्श भी उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा, महिला स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से 'शक्ति हेल्प बूथ' भी विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन बूथों पर महिला श्रद्धालुओं को ठहरने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा परामर्श तक की सुविधा मिल सकेगी।

## क्यूआरटी गश्त में महिला पुलिस अनिवार्य, रात में भी रहेंगी तैनात

कांवड़ मार्गों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीमों को सक्रिय किया गया है। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक क्यूआरटी में महिला पुलिसकर्मी अनिवार्य रूप से शामिल हों। चाहे वह दिन की ड्यूटी हो या रात की. रात में महिला पुलिसकर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति से महिला कांवड़ियों को सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों का अहसास हो सकेगा।

## मेरठ जोन में सबसे बड़ा महिला बल तैनात

कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों में से एक मेरठ जोन में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ और गाज़ियाबाद जैसे जिलों में कुल मिलाकर 3,200 महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। इन जिलों में यात्रा मार्गों पर नियमित गश्त के अलावा, संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर कुछ किलोमीटर पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं।

# कांवड़ यात्रा: पुलिस आयुक्त व डीएम ने कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कांवड यात्रा को लेकर जैसे-जैसे जलाभिषेक की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे-वैसे ही अधिकारियों की धकड़कनें भी बढ रही हैं। बीते चंद रोज में कांवडियों के उत्पाद को देखते हुए अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोट में हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी जिलाधिकारी से लेकर पुलिस आयुक्त, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडीसीपी यातायात तक सभी अधिकारी सड़कों पर रहे। अधिकारियों ने कांवड मार्ग, कंट्रोल रूम के अलावा कांवड मार्ग व शिविरों में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं अधिकारियों ने इस दौरान बैरीकेट लगने के बाद यातायात व्यवस्था को भी परखा।

पुलिस आयुक्त जे. रविन्द गौड ने कांवड यात्रा को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सोमवार देर रात मेरठ तिराहा से सीमापुरी बॉर्डर एवं डॉबर तिराहा तक पड़ने वाले कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस

मनोज शर्मा

आयुक्त ने शालीमार गार्डन, साहिबाबाद व लिंक रोड थाने का भ्रमण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। इसके अलावा मंगलवार सुबह जिलाधिकारी दीपक मीणा और एडिशनल कमिश्नर पुलिस आलोक प्रियदर्शी ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारी लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे और कांवड की तैयारियों का जायजा लेते हुए छोटे हरिद्वार मुरादनगर नहर पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान वहां तैनात एनडीआरएफ और पीएसी की टीम को पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग व मुरादनगर गंगनहर घाट पर तैनात अधिकारियों को भी जरूरी दिशा-निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान गंगनहर घाट पर आने वाले यात्री एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने को लेकर भी निर्देश दिये गए। साथ ही गंगनहर घाट पर तैनात टीमों को किसी भी संभावित प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया। इसके अलावा धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर जोन द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम एवं पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना नन्दग्राम क्षेत्रान्तर्गत कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। डीसीपी सिटी ने निरीक्षण के दौरान दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित लेन पर यातायात का नियमन करते हुए यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कांवड मार्ग का

निरीक्षण करने निकले अधिकारियों ने मेरठ रोड स्थित कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

## राहत केंद्र और सुविधाएं

कांवड़ियों की सुविधा के लिए मेरठ जोन में 838 अस्थायी सहायता केंद्र, 184 विश्राम जोन, 150 जल वितरण टैंकर, 30 एम्बुलेंस वाहन और 20 प्राथमिक उपचार शिविर तैयार किए गए हैं। प्रत्येक सहायता केंद्र पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, आराम और दिशा-निर्देश की समुचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही, खोया-पाया केंद्र और आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी जगह-जगह प्रदर्शित की जा रही है।

## सावन के सभी सोमवार को लेकर सजगता

सावन के महीने में दूधेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। सोमवार के दिन भीड़ कई गुना बढ़ जाती है, श्रद्धालुओं की लाइन मंदिर परिसर के बाहर जीटी रोड तक लग जाती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह के परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने महीने के सभी सोमवार के लिए दूधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास क्षेत्र में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके अनुसार, ये प्लान रविवार रात दस बजे से लागू होकर सोमवार की देर रात अभिषेक की समाप्ति तक रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने बताया कि श्रद्धालुओं की लाइनें मंदिर से फ्लाईओवर नीचे तक लग जाती हैं। डायवर्जन लागू होने से लोग जाम से बच सकेंगे। बैरिकेडिंग करके वाहनों को आगे जाने से रोक दिया जाएगा, जिसकी पुलिस व्यवस्था ने की है। इस दौरान ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर के नीचे

जस्सीपुरा, हापुड़ तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवगमन पूरी तरह से बंद रहेगा। चौधरी मोड़ की ओर से हापुड़ तिराहा व मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले हल्के व भारी सहित सभी प्रकार के वाहनों को घंटाघर फ्लाईओवर के ऊपर से भेजा जाएगा। इसी प्रकार हापुड़ तिराहा से आगे घंटाघर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। विजयनगर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन गौशाला फाटक और चौकी बैरियर से आगे दूधेश्वरनाथ मंदिर की ओर प्रतिबंध रहेगा।

## मंदिर तक पैदल आना होगा

दूधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास किसी को भी वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूधेश्वरनाथ मंदिर पर चौधरी मोड़ की ओर से श्रद्धालु अपने वाहनों को रामलीला मैदान में खड़ा कर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर तक पैदल आएंगे। इसी तरह विजयनगर की ओर से जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को मिलिट्री ग्राउंड में खड़ा करेंगे। यहां से उन्हें मंदिर तक पैदल जाना होगा। हापुड़ चुंगी व पुराना बस अड्डा की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को नवयुग मार्केट के मार्ग पर खड़ा करेंगे। फिर उन्हें यहां से मंदिर तक पैदल चलना होगा।

## मस्जिद व शराब की दुकान ढकी

मेरठ रोड पर रूट डायवर्जन करने के साथ ही कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी शराब के ठेकों को पर्दे से ढक दिया गया है। केवल कांवड़ मार्ग ही नहीं, उससे कनेक्ट होने वाले रास्तों पर भी शराब के ठेकों को पर्दे में रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद के सामने भी टेंट के जरिए पर्दे लगाए गए हैं।

## नहीं चले भारी वाहन

ट्रैफिक पुलिस का शुक्रवार रात से लागू भारी वाहनों का डायवर्जन प्लान के बाद शनिवार को दिल्ली-मेरठ रोड और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहा। हालांकि सुबह के वक्त कुछ भारी वाहन इन मार्गों पर नजर आए। लेकिन बाद में पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें मेरठ रोड और एक्सप्रेसवे पर नहीं जाने दिया। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है।

# कांवड़ यात्रा का रावण से क्या है कनेक्शन, कैसे शुरू हुई जलाभिषेक की परंपरा?

कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है कि किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण, महाविष्णु के छठें अवतार भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि, महर्षि मार्कंडेय, महारथी कर्ण और 61 नयनार संतों में से एक संत कनप्पा जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने महादेव को प्रसन्न किया था।

पवित्र सावन का महीना जारी है। जलाशयों से शिवालयों तक दिखाई दे रहे हैं जत्थे ही जत्थे। आसमान जल से भरे बादलों से ढका हुआ है, धरती पर सावन की झड़ी लगी हुई है। कभी उमस है, कभी तपिश तो कभी रिमझिम-रिमझिम।

फिर भी महादेव शिव को मन बसाकर उनके अभिषेक के लिए कांवड़ लेकर चले शिवभक्तों की भक्ति की थाह पाना कठिन है। वह चले जा रहे हैं, बिना रुके-बिना खके। अपनी कांवड़ को कांधों पर लटकाए, अपने शिवालय की ओर।।। जहां महादेव उनकी प्रतीक्षा में हैं, और सड़क के

मुकुल पंडित

किनारों पर चल रहे इन श्रद्धालुओं के भक्त हृदय का भाव ऐसा है कि अपने शिव के ही समान वे भी उनके ही नामधारी हो जाते हैं और 'भोले' कहलाते हैं। शिव को समर्पित और कांवड़ लेकर जल लेने जा रहे कांवड़िये शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। रावण संहिता में इस विषय में आया है कि जो भक्त शिव का अनवरत नाम जप करता रहता है और उनका ही ध्यान करता रहता है, वह खुद भी शिव के समान ही हो जाता है। इसलिए शैव नागा साधुओं को आप देखें तो वह अपने आप में शिवजी की ही छाया नजर आते हैं।

## कांवड़ यात्री कहलाते हैं भोले

कुछ अराजक घटनाओं को छोड़ दें तो महादेव के वक्त वाकई होते 'भोले' ही हैं। मन का विश्वास जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इसे सिर्फ भक्त और भगवान ही समझ सकते है, बीच की कड़ी के लोग इसे या तो नकार देते हैं, या फिर लीला कहकर आनंद लेते हैं। कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की ओर से अपने शिव के लिए की जा रही एक'लीला' ही तो है, जहां कंधे पर आस्था के दंड में सिर्फ अभिषेक के लिए गंगाजल से भरे कलश नहीं बंधे हैं, बल्कि एक ओर बंधा है समर्पण और दूसरी ओर बंधी है भक्ति।

फिर क्या फर्क पड़ता है कि कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पुराण में मिलता है या नहीं, अगर महादेव शिव सिर्फ 'एक लोटा जल' से विष्णु द्रोही रावण पर प्रसन्न हो सकते हैं तो हम तो रामजी के बालक और शिवजी के दास हैं, हम पर शिव क्यों न प्रसन्न होंगे? जरूर होंगे।

## पौराणिक ग्रंथों में कांवड़ यात्रा?

वाकई में कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है कि किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण,

महाविष्णु के छठें अवतार भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि, महर्षि मार्कंडेय, महारथी कर्ण और 61 नयनार संतों में से एक संत कनप्पा जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने महादेव शिव को बड़ी सरल-सहज और आसान विधि से पूजन कर प्रसन्न किया था। रावण और भगवान परशुराम द्वारा तो शिवजी के लिए कांवड़ लाकर भी उनका जलाभिषेक करने का प्रसंग लोककथाओं में मिलता है, हालांकि पुराणों में हर जगह इनके द्वारा की गई विधिवत पूजा का ही वर्णन मिलता है, जिसमें पंचोपचार पूजन से लेकर, षोडशोपचार पूजन तक का वर्णन मिलता है, फिर भी कांवड़ द्वारा जल लाकर शिवजी के अभिषेक का वर्णन नहीं मिलता है।

## राम कथा में मिलता है कांवड़ शब्द का जिक्र

हालांकि कांवड़ शब्द का जिक्र रामायण में मिलता है। जहां राजा दशरथ द्वारा गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। इस प्रसंग में जब श्रवण कुमार के चरित्र का वर्णन आता है तब कांवड़ का जिक्र होता है। जहां पता चलता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता-पिता को कांवड़ में बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। कांवड़ असल में तराजू जैसी आकृति का एक नमूना होता है। श्रवण ने अपने माता-पिता को दोनों ओर बिठा लिया और कांवड़ कंधे पर रखकर चला।

## प्राचीन काल की तीर्थ यात्रा की परंपरा

प्राचीन काल में तीर्थयात्रा का एक नियम होता रहा है, जिस तीर्थ में जाते हैं, वहां का जल लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह हर तीर्थ का जल इकट्ठा होता जाता है। तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव गंगा सागर या फिर सागरतट पर बसा कोई तीर्थ होता था। रामायण काल में सोमनाथ और प्रभास तीर्थ का बहुत महत्व था, जो कि सागर तट पर था। इसी तरह गंगासागर तीर्थ जहां कपिल मुनि का आश्रम था, वह भी अंतिम तीर्थ हुआ करता था। श्रद्धालु इन अंतिम तीर्थों में पहुंचकर सभी तीर्थों का जल चढ़ाया करते थे।

श्रवण कुमार के माता-पिता के पास एक छोटे कमंडल में सभी तीर्थों का जल था, लेकिन

अयोध्या की बाहरी सीमा पर श्रवण कुमार की मृत्यु होने के बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे।

## कांवड़ यात्रा और लोककथाएं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र में दशानन रावण से जुड़ी कई लोककथाएं प्रचलित हैं। यहां नोएडा के पास बिसरख गांव को रावण की जन्मस्थली बताया जाता है। मेरठ को मयराष्ट्र बताते हुए उसे रावण की ससुराल बताया जाता है। यहीं बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पर खुद रावण ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर शिवजी का जलाभिषेक किया था, जबकि रावण से भी सैकड़ों वर्ष पहले भगवान परशुराम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और 108 कलश से उनका अभिषेक किया था।

## भगवान परशुराम का कांवड़ से संबंध?

हालांकि सीधे तौर पर किसी पौराणिक संदर्भ में इन स्थानों का जिक्र नहीं मिलता है। फिर भी इन जगहों का मान्यताओं और लोककथाओं में परशुराम और रावण के नाम कैसे जुड़ गए, इस बारे में कहना मुश्किल है। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को जीतकर सारी पृथ्वी जीत ली थी। फिर शिव जी ने उन्हें रक्तपात से रोका और अगले अवतार की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने सारी पृथ्वी भगवान शिव, जो उनके गुरु भी थे उन्हें दान कर दी और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। शिव जी ने अपना फरसा सागर में फेंक दिया और फरसा जहां गिरा, वहां जल दोनों तरफ किनारे हट गया और जो भूमि बाहर आई उसे केरल कहा गया।

## दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में प्रसिद्ध है कथा

परशुराम जी ने वहां शिवलिंग स्थापित किया और सागर से कलश भरकर जल लाते थे और उनका अभिषेक करते थे। केरल के वडक्कूनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना परशुराम द्वारा ही बताई जाती है। संभवतः इसी प्रसंग ने उन्हें आगे चलकर पहला कांवड़िया घोषित किया होगा। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में यह कथा प्रचलित है।

## रावण संहिता में मिलता है रावण की शिवपूजा का जिक्र

उधर, रावण की शिव पूजा का विस्तृत जिक्र रावण संहिता में मिलता है। एक बार रावण महिष्मती क्षेत्र पर विजय पाने के लिए गया। रास्ते में नर्मदा नदी पड़ी। रावण ने इस सुंदर स्थल पर शिवलिंग स्थापित कर शिव आराधना करने की ठानी। वह नर्मदा नदी से जल लाकर शिव अभिषेक कर रहा था। इसी दौरान नर्मदा में सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने अपने एक हाथ के बल से नर्मदा की धारा को रोक दिया।

रावण जिस स्थान से जल भर रहा था, अचानक वहां नदी का पानी वेग से बढ़ा और फिर वह स्थल जल विहीन हो गया। तब रावण पूजा बीच में छोड़कर इसकी वजह जानने पहुंचा और इस तरह उसका सहस्त्रार्जुन से युद्ध हुआ। खैर, रावण ने भी शिव जी को कलश में जल लाकर उनका अभिषेक किया था, इसलिए रावण की भी मान्यता कांवड़ यात्रा की किवदंती के तौर पर सामने आती है।

## स्कंद पुराण में जलाभिषेक का जिक्र

स्कंद पुराण में शिव उपासना के लिए रावणोपाख्यान सर्ग में एक जिक्र आता है, जहां शिवगण नंदी और रावण की बातचीत होती है।

# संत कनप्पा की सरल शिव भक्ति

बात सरल शिवपूजा की आती है तो दक्षिण भारत के नयनार संतों में शामिल संत कनप्पा भी याद आते हैं। वह भील जाति के शिकारी थे, लेकिन जब शिव से उनकी लगन लगी तो वह अपने अनुसार उनकी पूजा में रम गए। कहते हैं कि वह जो खुद खाते वही शिव जी को अर्पित करते थे। एक दिन उन्होंने हिरण का मांस पकाया। जंगली पुष्प से माला बनाई और दोनों हाथ में मांस भूनकर पत्तों पर रखकर शिवजी की ओर चले। फिर सोचा कि पानी तो लेना ही भूल गया। इसलिए वह पास ही बह रही स्वर्णमुखी नदी पर पहुंचे, लेकिन पानी ले कैसे? तब संत कनप्पा ने नदी में डुबकी मारी और मुख में पानी भर लिया। फिर शिवलिंग को उसी मुंह में भरे पानी से नहलाया, उन्हें मांस चढ़ाया और वनफूलों की माला भी अर्पित कर दी। शिव उनके इस भोलेपन से इतना प्रसन्न हुए कि प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। ऐसे होते हैं शिव के असली भोले भक्त। इसलिए शिवजी की कांवड़ यात्रा का जिक्र पुराणों में मिले न मिले, किसी रावण ने कांवड़ पहले चढ़ाई हो या नहीं, शिवभक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो बस इतनी सी बात है, वे शिव के हैं और शिव उनके हैं। हर-हर महादेव

इस स्थान पर नंदी कहते हैं कि जो प्राणी जलाशय से शिवालय तक पैदल ही गमन करता है, और फिर जल ले जाकर शिवालय को धोकर साफ करता है, वह बिना किसी विधान की पूजा के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्कंद पुराण में कांवड़ यात्रा का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि 'जलाशय से जल लेकर शिवालय तक की यात्रा'। संभवतः आगे चलकर यही व्याख्या कांवड़ यात्रा के संदर्भ में ली गई होगी।

## ग्रामीण परंपरा है कांवड़ यात्रा

हालांकि कांवड़ यात्रा विशुद्ध ग्रामीण परंपरा है और इसकी शुरूआत इधर के आधुनिक काल में ही कभी हुई हो, इसकी अधिक संभावना हो सकती है। इसके दो कारण है। कांवड़ यात्रा का समय सावन मास का है, जो चौमासे यानी चतुर्मास के बीच में आता है। प्राचीन मान्यता और नियम तो ये रहा है कि चौमासे में यात्राएं स्थगित रहती हैं। इसका जिक्र तो रामायण में भी मिलता है कि, चौमासे के दौरान देवी सीता की खोज अभियान को रोक दिया गया था। ऐसे में किसी दूर-दराज की यात्रा की परंपरा प्राचीन काल से मिलती हो, ऐसा तो कम ही हो सकता है। दूसरी वजह ये है कि इस दौरान ग्रामीण किसान परिवार को खेतों की ओर से अधिक चिंता नहीं रहती है। वर्षा काल होने के कारण खेती बंद रहती है। पानी भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसे में यह समय गांवों में पूजा-पाठ और मनौतियों का होता है। ये मनौती कुछ भी हो सकती हैं। संतान प्राप्ति, बेटी का विवाह, रोग नाश, संपत्ति और कोई भी कामना पूर्ति के लिए मानी जाने वाली सौगंध। अक्सर मनौतियां या तो देवी माता से जुड़ी होती हैं, या शिव जी से। शिवजी से जुड़ी मनौतियां इसी तरह की सरल होती हैं, जिसमें उनका अभिषेक गंगाजल से कराने की मनौती सबसे आम है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार ये संख्या तय कर लेते हैं कि कितने कलश गंगाजल से वह शिवजी का जलाभिषेक करेंगे। इस तरह की मनौतियों के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं ही हैं। स्कंदपुराण के माहेश्वरखंड में इसका जिक्र आता है, जहां लोमश ऋषि बताते हैं कि शिवजी के मंदिर का मार्जन (सफाई) करने वाले उनके गणों में शामिल हो जाते हैं। उनको चंवर भेंट करने वाले अपने कुल को तार देते हैं। शिवजी को धूप अर्पित करने वाले पिता व नाना दोनों कुलों को मुक्ति मार्ग बताते हैं। दीपदान करने वाले तेजस्वी होते हैं, जो स्त्रियां चौक पूरती हैं वे शिवधाम प्राप्त करती हैं और जो तेज आवाज वाले सुंदर मधुर घंटे चढ़ाते हैं, वह कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ये सारी मान्यताएं जो पुराणों से आई हैं, वही शिव पूजन को महत्वपूर्ण और सरल बनाती हैं।

# अपनी पहचान जाहिर करने में कैसी शर्म !

अरुण शर्मा

भगवान शंकर के प्रिय माह सावन की शुरूआत 11 जुलाई से हो गई है। सावन की शुरूआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया। कांवड़ यात्रा में शिवभक्त नंगे पांव हाथ में कांवड़ लेकर लंबी दूरी तय करके शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग में जाते हैं और पवित्र नदियों के जल से उनका अभिषेक करते हैं।

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। कांवड़ यात्रा का विराट रूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस मार्ग से निकलते हैं। इस मार्ग में भगवान शिव के कई बड़े प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहां पर श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस मार्ग से गंगाजल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर तनाव बढ़ गया है। असल में, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा गांव में योग साधना आश्रम के संचालक और सनातन धर्म के प्रचारक स्वामी यशवीर महाराज पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ मार्ग पर कुछ लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर ढाबे और दुकानें चलाकर शिव भक्तों को धोखा दे रहे हैं। पहचान छुपाकर धोखा देने वाले कई मामले सामने आने के बाद पिछले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी किए कि कांवड़-यात्रा के मार्ग के ढाबे, होटल, रेस्तरां, दुकानदार, खोमचेवाले स्पष्ट नाम पट्टिका लगाएंगे। सरकार का मंतव्य है कि कांवड़ियों की आस्था और श्रद्धा खंडित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इस साल भी उप्र और उत्तराखंड की सरकारों ने पिछले साल की भांति आदेश जारी किए हैं।

ताजा प्रकरण यह है कि, स्वामी यशवीर महाराज और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कांवड़ मार्ग स्थित दिल्ली-दून हाईवे स्थित पंडित वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। वास्तव में, ढाबा मुस्लिम का था, लेकिन बोर्ड पर लिखा था-'पंडित का शुद्ध वैष्णो ढाबा।' यानी पहचान छिपाने का अपराध किया गया था। पंडित वैष्णो ढाबे को सनव्वर नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता है। इस ढाबे में उसका बेटा आदिल और जुबैर समेत दो अन्य लोग भी काम करते हैं।

कहा जा रहा है कि यशवीर महाराज और अन्य ने ढाबे के मालिक और कर्मचारियों की धार्मिक पहचान जांचने के लिए पैंट उतरवाई। विवाद यहीं से भडका। आग में घी डालते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पहचान वाले मामले को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ने का काम किया। हसन ने कहा कि, "मैं पूछना चाहता हूं कि

**असल में, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा गांव में योग साधना आश्रम के संचालक और सनातन धर्म के प्रचारक स्वामी यशवीर महाराज पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग करते रहे हैं।**

क्या आम नागरिकों को अधिकार है कि वह किसी दुकानदार की पैंट उतरवाकर चेक कर सकते हैं? क्या पहलगाम में आतंकियों ने पैंट नहीं उतरवाई थी? ऐसा करने वाले और पहलगाम के आतंकवादियों में क्या अंतर रह गया?"

उस ढाबे पर यह घटना हुई अथवा नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन प्रकरण को 'सांप्रदायिक मोड़' दे दिया गया। पहलगाम एक सुनियोजित आतंकी कृत्य था। इन दोनों घटनाओं की तुलना करना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि यह समाज में धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने का प्रयास भी है।

और जहां तक बात पहचान छुपाने या धोखा देने की है तो यह धंधा लंबे समय से चल रहा है। जुलाई, 2021 में गाजियाबाद में दो ऐसे मुसलमान दुकानदारों का पता चला था, जो हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे। इनमें एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी में है, जिसका नाम है 'न्यू अग्रवाल पनीर भंडार।' इस दुकान का मालिक है मंजूर अली। दूसरी दुकान 'लालाजी पनीर भंडार' के नाम से है। इसका मालिक ताहिर हुसैन है। इन दोनों का कहना था कि हिंदू नाम रखने से ग्राहक कम पूछताछ करते हैं और धंधा अच्छा चलता है। यानी ये धंधे के लिए हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे थे। इनकी पोल तब खुली जब कुछ लोगों को पता चला कि इनका जीएसटी नंबर इनके असली नाम से है। स्थानीय दुकानदारों ने इनका विरोध किया तो इन लोगों ने अपनी दुकानों के नाम बदल लिए हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रा के समय जब नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी हुए थे, तो खूब हंगामा मचा था। उस समय सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और समाचार चैनलों तक में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कैसे एक आदेश के चलते रातों रात मुजफ्फरनगर का 'संगम शुद्ध शाकाहारी होटल' बन गया 'सलीम ढाबा।' 'मां भवानी जूस कार्नर' का नाम हो गया 'फहीम जूस केंद्र।' 'टी प्वाइंट' का नाम हो गया 'अहमद टी स्टाल।' ऐसे ही 'नीलम स्वीट्स' का मालिक निकला मोहम्मद फजल अहमद। 'अनमोल कोल्ड ड्रिंक्स' का मालिक है मोहम्मद कमर आलम। खतौली के 'चीतल ग्रैंड' के बाहर एक बोर्ड लग गया है, जिस पर लिखा गया है- शारिक राणा डायरेक्टर। सहारनपुर में चल रहे 'जनता वैष्णो ढाबा' का मालिक है मोहम्मद अनस सिद्दीकी। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव निवासी वसीम अहमद ने पिछले साल पहचान जाहिर होने के बाद अपना 'गणपति' ढाबा बेच दिया।

एक रिपोर्ट के अनुसार देहरादून-नैनीताल राजमार्ग पर 20 से अधिक ढाबे ऐसे हैं, जो हिन्दू देवी-देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले मुसलमान हैं। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर चिडियापुर और समीरपुर गंग नहर रोड पर भी ऐसे हिंदू नामधारी ढाबे हैं, जिनके मालिक मुसलमान हैं। मेरठ, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, मुंडा पांडे हाईवे पर भी दर्जनों ऐसे ढाबे चल रहे हैं, जिनके मालिक मुसलमान हैं। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, धोखा देने के लिए ये लोग होटल के अंदर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र भी रखते हैं, ताकि हिंदू यात्रियों को लगे कि वे किसी हिंदू होटल में ही खाना खा रहे हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक ऑनलाइन पैसा देता है, तब पता चलता है मालिक मुसलमान है। इन ढाबों और होटलों में काम करने वाले लोगों के नाम राजू, विक्की, गुड्डू, सोनू जैसे होते हैं। ये लोग तिलक भी लगाते हैं और कलावा भी बांधते हैं। यह धोखा नहीं तो क्या है? मुजफ्फरनगर के पंडित वैष्णो ढाबे पर काम करने वाले तजमुल ने खुद को गोपाल बताया था। हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार में स्कैनर से पेमेंट गुलफाम नाम के अकाउंट में जाने का मामला बीते दिनों प्रकाश में आया है।

अहम सवाल यह है कि पहचान छुपाकर व्यापार करने के पीछे कोई मजबूरी है या षडयंत्र? मुस्लिम व्यक्ति को अपने नाम से दुकान या ढाबा खोलने में क्या दिक्कत है? अपने-अपने धर्म के हिसाब से नाम लिखकर लोग दुकान खोलेंगे या व्यापार करेंगे तो ग्राहक अपनी मजी से दुकान पर जाएगा और जिसे जहां से जो खरीदना होगा, वो वहां से खरीदेगा। लेकिन पहचान छुपाकर व्यापार या कोई अन्य कार्य करना कानून और नैतिक तौर पर गलत और अपराध है। ऐसी घटनाएं और प्रकरण प्रकाश में आने के बाद संदेह और अविश्वास का माहौल बनता है। जो सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर दिक्कतें पैदा करता है।

बात जब खाने पीने की हो तो मामला गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। खानपान के पीछे व्यक्तिगत रूचि, संस्कार, धर्म-कर्म और आस्था की पृष्ठभूमि और भूमिका होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन-प्रशासन के नेम प्लेट के आदेश से किसी की भावनाएं आहत नहीं होतीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि खानपान के दुकानदारों को अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाना होगा, जहां आसानी से उसे देखा जा सके।

वैसे भी ये मसला हिंदू-मुस्लिम, धार्मिक भेदभाव या किसी की आजीविका की बजाय सीधे तौर भावनाओं और ग्राहक के अधिकार से जुड़ा है। जो करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उन सबको रास्ते में भोजन कैसा मिले? कैसा भोजन वो खाएं? ये उनकी स्वतंत्रता है। जब मुसलमान हलाल प्रमाणपत्र देखकर ही कोई सामान खरीदता है, तब हिंदू भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता है!

# बेटियों के लिये मोह बढ़ना संतुलित समाज का आधार

इक्कीसवीं सदी की चौखट पर खड़ी दुनिया में बड़े व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इंसानी रिश्तों की अहमियत को लेकर भी नई सोच पनप रही है। अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है।

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

दुनियाभर में माता-पिता आमतौर पर अब तक बेटियों की तुलना में बेटों को ज्यादा पसंद करते आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म, महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब लड़के की तुलना में लड़कियों को अधिक पसंद किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह कम है और संभवतः लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह ज्यादा है। नए साक्ष्य एवं अध्ययन इस बदलाव का संकेत देते हैं, जो संभवतः बढ़ते एकल परिवार परम्परा, तथाकथित आधुनिक-सुविधावादी जीवनशैली एवं कैरियर से जुड़ी प्राथमिकताओं के चलते लड़कों से जुड़े एक सूक्ष्म भय, उपेक्षा एवं उदासीनता को उजागर करते हैं। 'द इकोनॉमिस्ट' द्वारा ताजा प्रकाशित रिपोर्टों में, लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में कुछ ऐसे ही दिलचस्प रुझान सामने आए हैं, जिसमें लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में माता-पिता अब लड़कों की तुलना में लड़कियों को भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक पसंद कर रहे हैं। विकासशील देशों में, लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह कम हो रहा है, जबकि अमीर देशों में लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक भूमिकाओं को लेकर विचारों में अंतर बढ़ता जा रहा है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना

में दो स्थान नीचे है, और इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 प्रतिशत है। वर्तमान प्रगति की दर से, पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, जो दशार्ता है कि प्रगति की समग्र दर धीमी है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि दुनिया भर में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत के लिये लैंगिक समानता की दिशा में दो पायदान की गिरावट का सबसे बड़ा कारण महिला समानता को लेकर चल रहे आन्दोलन है। भारत की बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक में बुलंदियां छू रही हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में उल्लेखनीय भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसे सराहनीय पहल के जरिए बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी की चौखट पर खड़ी दुनिया में बड़े व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इंसानी रिश्तों की अहमियत को लेकर भी नई सोच पनप रही है। अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है? दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता, परिवार सार-संभालकर्ता, माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी निर्वाहकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिये अधिक संवेदनशील है। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं।

पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। भारत में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। जबकि सदियों से भारत की समाज-व्यवस्था एवं परिवार-परम्परा पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। जिसके चलते शिशु लिंग अनुपात में असंतुलन बढ़ता गया है। देश में हुई 2016 की जनगणना में लड़कों की तुलना में लड़कियों की घटती संख्या के आंकडे. चौंकाते ही नहीं बल्कि दुखी भी करते हैं। जिस तरह से लड़के-लड़कियों का अनुपात असंतुलित हो रहा है, उससे ऐसी चिन्ता भी जतायी जाने लगी है कि यही स्थिति बनी रही तो लड़कियां कहां से लाएंगे? हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में 2016 में प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले महज आठ सौ छह लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है।

जन्म से पहले ही पता चल जाए कि लड़की यानी बालिका पैदा होगी तो माता-पिता उसकी जान लेने से भी नहीं कतराते। कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं इसी सोच का परिणाम बनी। पिछली सदी में समाज के एक बड़े वर्ग में यह एक विभीषिका ही थी कि परिवार की धुरी होते हुए भी नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं था जिसकी वह अधिकारिणी थी। उसका मुख्य कारण था सदियों से चली आ रही कुरीतियाँ, अंधविश्वास व बालिका शिक्षा के प्रति संकीर्णता। कितनी विडम्बना है कि देश में हम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा बुलन्द करते हुए एक जोरदार मुहिम चला रहे हैं उस देश में लगातार बालिकाओं की संख्या घटने का दाग लगता रहा है। यह दाग 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प पर भी लगा है और यह दाग हमारे द्वारा नारी को पूजने की परम्परा पर भी लगा है। लेकिन प्रश्न है कि हम कब बेदाग होंगे? लेकिन अब इस संकीर्ण सोच में बदलाव आना एक सुखद संकेत है। अच्छे भविष्य के लिए हम बेटियों की पढ़ाई से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे हमारे संकल्प को बताते हैं, हमारी सदिच्छा को दिखाते हैं, भविष्य को लेकर हमारी सोच को जाहिर करते हैं, लेकिन वर्तमान की हकीकत इससे उलट है, इसे बदलने में अभी भी लम्बा सफर तय करना होगा। बालिकाएं पढ़ाई में अपने झंडे भले ही गाड़ दें, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की क्रूरताएं कई तरह की हैं। शताब्दियों से हम साल में दो बार नवरात्र महोत्सव मनाते हुए कन्याओं को पूजते हैं। लेकिन विडम्बना देखिये कि सदियों की पूजा के बाद भी हमने कन्याओं को उनका उचित स्थान और सम्मान नहीं दे पाये हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए।

भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को लिंग समानता के वैश्विक आंदोलन की किसी भी तरह अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वैश्विक लैंगिक अंतर का आकलन और तुलना करने के लिए एक समझने योग्य ढांचा प्रदान करके और उन देशों को उजागर करके जो इन संसाधनों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप से विभाजित करने में रोल मॉडल हैं, रिपोर्ट अधिक जागरूकता के साथ-साथ नीति निमार्ताओं के बीच अधिक आदान-प्रदान के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। भारत में समान संपत्ति अधिकार लागू करने, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। तभी भारतीय समाज में लिंगभेद की मानसिकता खत्म होगी और लैंगिक समानता की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी के लिये बालिकाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आधार बन सकेगी।

# जीवन को सार्थक बनाते हैं गुरू

**गुरुकुल में जो अध्यापक होते थे, वह अपने आपको गुरु की भूमिका में लाने के लिए ज्ञान की साधना करते थे। एक ऐसा ज्ञान जो समाज को सार्थक दिशा का बोध करा सके। उस समय वर्तमान की तरह स्कूल नहीं होते थे। क्योंकि स्कूलों की प्रणाली विदेशी प्रणाली है।**

अजीत शर्मा

गुरु बिन ज्ञान न उपजै गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को गुरु बिन मिटै न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता और न ही मोक्ष मिल सकता है। गुरु के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही दोष मिट पाते हैं। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संवारने के लिए गुरू का होना बहुत ही आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को धारण करने वाला व्यक्ति प्रेरणापुंज की तरह ही होता है।

उनके प्रत्येक शब्द सकारात्मक दिशा का बोध कराने वाला होता है। हम प्रायः सुनते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु यानी सम्पूर्ण क्षेत्रों में विश्व का मार्ग दर्शन करने वाला, लेकिन क्या हमने सोचा है कि भारत का वह कौन सा गुण था, जिसके कारण विश्व के अंदर भारतीय प्रतिभा और क्षमता का बोलबाला था। इसका उत्तर आज भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन यथार्थ यही है कि इसके पीछे मात्र भारतीय गुरुकुल ही थे। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें बालक के सम्पूर्ण विकास की अवधारणा और संरचना होती है। उस समय के हिसाब से गुरुकुलों में विश्व की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। छात्रों का समग्र विकास किया जाता था। चाहे वह ज्ञान, विज्ञान का क्षेत्र हो या शारीरिक शिक्षा की बात हो या फिर नैतिक और व्यावहारिक संस्कारों की ही बात हो। गुरुकुल की शिक्षा बहुमुखी प्रतिभा का विकास करती थी। आज देश में कई गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें बहुत आश्चर्यजनक प्रतिभा संपन्न बालकों का निर्माण भी हो रहा है। पिछले समय गूगल बॉय के रुप में चर्चित होने वाला बालक इन्हीं गुरुकुलों की देन है। गुजरात के कर्णावती में हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में ऐसे नन्हे प्रतिभाशाली छात्रों को देखकर विदेशी भी चकित हैं। हमारे देश को वास्तव में गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, क्योंकि यही भारत की वास्तविक शिक्षा है और इसी से छात्रों का समग्र विकास हो सकता है।

गुरुकुल में जो अध्यापक होते थे, वह अपने आपको गुरु की भूमिका में लाने के लिए ज्ञान की साधना करते थे। एक ऐसा ज्ञान जो समाज को सार्थक दिशा का बोध करा सके। उस समय वर्तमान की तरह स्कूल नहीं होते थे। क्योंकि स्कूलों की प्रणाली विदेशी प्रणाली है। इससे गुरु और शिष्य के

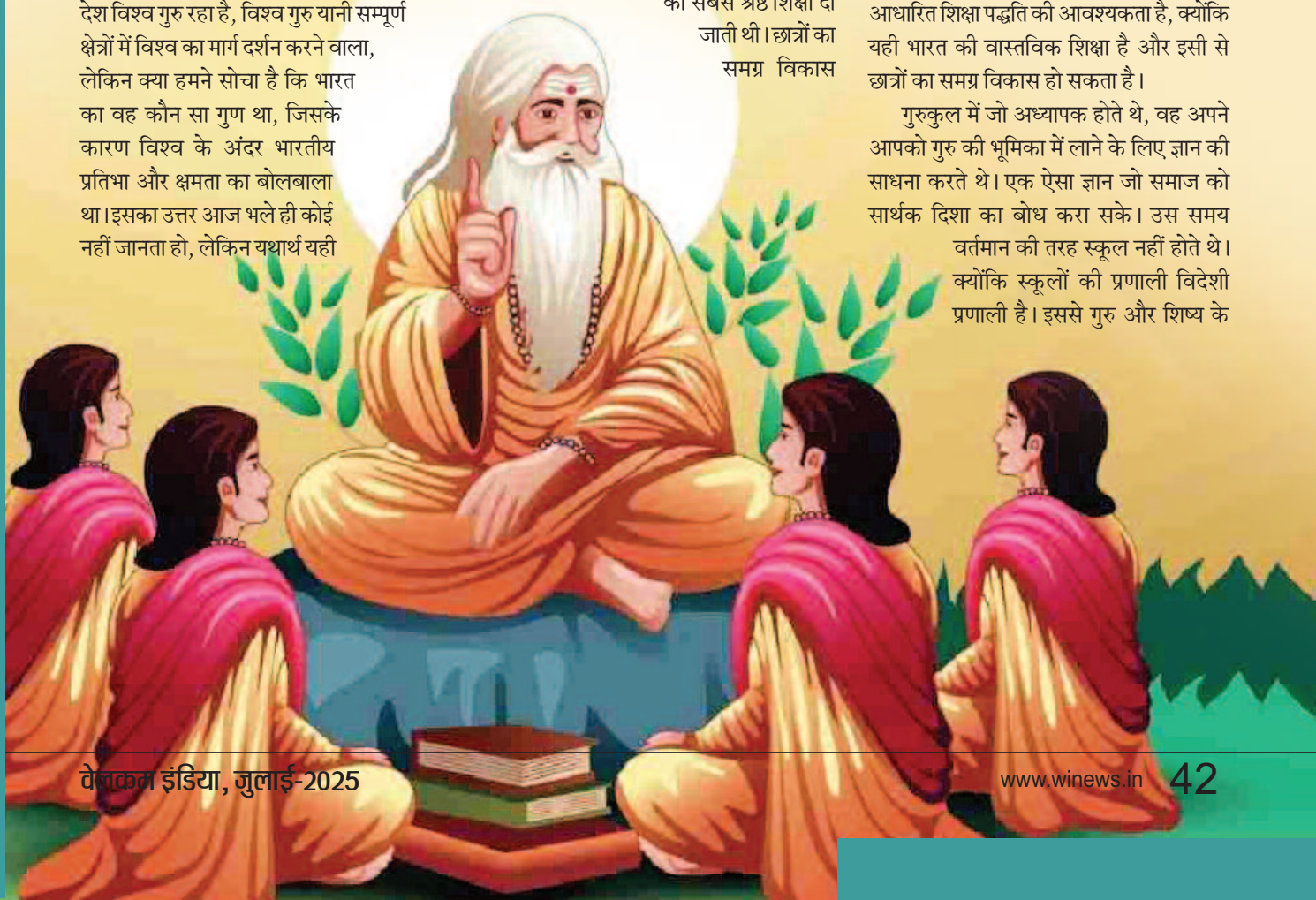

मध्य अपनत्व नहीं होता। गुरुकुल का अर्थ स्पष्ट है। वह गुरू का कुल यानी परिवार होता था। गुरु अपने शिष्य को अपने परिवार का सदस्य मानकर ही शिक्षा देता था। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ ही अंधकार को समाप्त करने वाला होता है। आज के स्कूल एक प्रकार के व्यापार केन्द्र ही हैं। पैसे को आधार मानकर शिक्षा देने का चलन हो गया है। इससे गुरु और शिष्य के बीच गुरुकुल जैसे संबंध नहीं बनते, क्योंकि इन स्कूलों में नैतिक व्यवहार की सीख नहीं दी जाती। शिष्य को ज्ञान नहीं, केवल शब्द पढ़ाए जाते हैं।

शिक्षा प्रणाली का किसी भी देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसका हमारे देश में नितांत अभाव महसूस किया जाता रहा है। शायद, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने शिक्षा नीति बनाने के बारे में कम चिन्तन किया। इसी कारण आज की नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी देने से वंचित किया जा रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि इतिहास कोई सौ या दो सौ सालों में नहीं बनते।

जहां तक भारत के दो सौ सालों के इतिहास की बात है तो इस दौरान भारत परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि उस कालखंड का इतिहास हमारा मूल इतिहास नहीं कहा जा सकता। अगर हमें भारत के इतिहास का अध्ययन करना है तो उस कालखंड में जाना होगा, जब भारत पर किसी विदेशी का शासन नहीं था। क्या आज यह इतिहास कोई जानता है, ... बिलकुल नहीं। उसको कोई बताता भी नहीं, क्योंकि उसको बताने से भारत का वही रूप सामने आएगा, जो विश्वगुरू भारत का था।

हम जानते हैं कि विश्व के प्रायः सभी देशों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वह उस देश के मूल भाव को संवर्धित करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा का मूल भी यही होना चाहिए कि उसमें उस देश का मूल संस्कार परिलक्षित हो। हमें पहले यह भी समझना होगा कि शिक्षा किसलिए जरूरी है? क्या केवल साक्षर होने या नौकरी के लिए पढ़ाई की जानी चाहिए अथवा इसके और भी गहरे मायने हैं? विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय वह केंद्र होते हैं, जहां विद्यार्थी को वैचारिक स्तर पर गढ़ने का कार्य किया जाता है।

विद्यार्थी को गढ़ने का कार्य केवल गुरू ही

कर सकते हैं। भारत के मनीषियों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य को समझा और गुरुकुल पद्धति पर बल दिया। पारिवारिक वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें आत्मनिर्भरता विकसित होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त करता था। उससे आत्मानुशासन की प्रवृत्ति का भी विकास होता था। महाभारत में गुरुकुल शिक्षा को गृह शिक्षा से अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की सफलता का मुख्य आधार गुरुकुल ही थे जो किसी न किसी महान तपधारी ऋषि की तपोभूमि तथा विद्यार्जन के स्थल थे।

गुरुकुल और समाज के मध्य पृथक्करण नहीं था। गुरु का कार्यक्षेत्र केवल गुरुकुल तक ही सीमित नहीं था अपितु उनके तेजोमय ज्ञान का प्रसार राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में था। उनकी विद्वता और उत्तम चरित्र तथा व्यापक मानव सहानुभूति की भावना के कारण उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली होती थी। गुरु के आचार-विचार में भेद नहीं होता था।

गुरुकुल में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थी के अन्तर्मन में झाँककर गुरु उसकी योग्यता, आवश्यकता एवं कठिनाइयों को भलीभांति समझते थे। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्तम मानस का निर्माण करना था। वस्तुतः स्वयं गुरु ही विद्यार्थियों के आदर्श थे जिनसे प्रेरित होकर वे उनका अनुसरण करते थे और संयमी, गम्भीर तथा अनुशासन युक्त जीवन का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में धौम्य, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, सांदीपनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम प्रसिद्ध रहे। बौद्धकाल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल जग प्रसिद्ध थे, जहाँ विश्वभर से मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करने आते थे और जहाँ गणित, ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, भौतिक आदि सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी।

प्रत्येक गुरुकुल अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र-शस्त्र सिखाने में तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शिक्षा देने में दक्ष था। भारतीय संस्कृति में कहा गया है 'सा विद्या या विमुक्तयेइ अर्थात् विद्या वही है जो हमें सब बंधनों से मुक्त कर दे। कहा जाता है कि जैसी शिक्षा दी जाएगी, देश का मानस उसी प्रकार का बनता जाएगा। इसलिए समाज को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे असली भारत का निर्माण हो सके। इसलिए इस ओर बहुत अच्छे प्रयास प्रारम्भ हो गए हैं।

# सावन मास का विशेष महत्व

**सावन मास में सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव की पूजा और भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ माना जाता है। शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने और शिव जी की विशेष पूजा करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है।**

## सावन सोमवार का महत्व क्यों है?

सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ माना जाता है। श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह व्रत व्यक्ति के कल्याण के लिए भी किया जाता है। सावन

रवि रंजन कुमार

सोमवार के दिन श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जैसे कि रुद्राभिषेक, शिव लिंग पर जल चढ़ाना और भगवान शिव की स्तुति करना। सावन माह में सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यह व्रत व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति के करीब ले जाता है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

## सावन सोमवार के व्रत के नियम

सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की नियमित पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत

रखने से विशेष लाभ मिलता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सावन सोमवार के दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भगवान शिव के सावन में विशेष अनुकंपा का अत्यधिक महत्व है, जिसे हिंदू पंचांग के पांचवें महीने में मनाया जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना और पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, और इस दौरान उनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

## भगवान शिव की पूजा विधि

भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी आवश्यक हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री में शिवलिंग या शिव की मूर्ति, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष माला, चंदन, कुमकुम, अगरबत्ती और दीपक, फूल (विशेषकर कमल और गुलाब), नैवेद्य (प्रसाद) आदि शामिल है।

## पूजा विधि

सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, साफ वस्त्र पहनें, अधिमानतः सफेद रंग के। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल या ताजा जल अर्पित करें, फिर कच्चे दूध से भोलेनाथ को स्नान करवाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भस्म, नैवेद्य अर्पण करें। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें।

## सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय

बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाएं और चावल का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श या मंदिर के चौखट का स्पर्श जरूर करें। इससे सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और किस्मत चमक उठती है।

## सावन और पौधारोपण

सावन के महीने में कुछ विशेष पौधों को लगाने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। बेलपत्र से घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मदार के पौधे से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आंवला का बहुत धार्मिक महत्व है । इससे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। धतूरा से घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होती और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।

# कॉटन साड़ी के साथ ट्राई करें ये 3 ज्वेलरी सेट क्लासी और एलिगेंट लगेगा आपका लुक

*कॉटन साड़ी के साथ भी कई ज्वेलरी डिजाइंस ऐसी होती हैं, जिनको वियर करने से आपके लुक में चार चांद लग सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसी ज्वेलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप कॉटन की साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं।*

जब भी साड़ी स्टाइल करने की बात आती है, तो जरूरी होता है कि आप साड़ी के फैब्रिक के हिसाब से ज्वेलरी को स्टाइल करें। ऐसा करने से आपका लुक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। ऐसे में कॉटन साड़ी के साथ भी कई ज्वेलरी डिजाइंस ऐसी होती हैं, जिनको वियर करने से आपके लुक में चार चांद लग सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसी ज्वेलरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप कॉटन की साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं। इनको वियर करने से आपका लुक क्लासी और एलिगेंट नजर आएगा।

## स्टोन वर्क वाली ज्वेलरी

कॉटन वाली साड़ी के साथ आप स्टोन वर्क वाली ज्वेलरी वियर कर सकती हैं। कॉटम साड़ी के साथ यह ज्वेलरी पहनने पर काफी अच्छी लगेगी। इसमें आपको नेकलेस और इयररिंग्स दोनों में स्टोन स्टड का डिजाइन मिलेगा। इसके साथ ही इसमें छोटे-छोटे पर्ल भी मिलेंगे, जिससे यह ज्वेलरी काफी क्लासी लगेगी। इससे आपका लुक अट्रैक्टिव नजर आएगा। मार्केट में आपको इस तरह की ज्वेलरी काफी कम पैसे में मिलेगा।

## घुंघरू वर्क वाली ज्वेलरी

घुंघरू डिजाइन वाली ज्वेलरी को भी आप कॉटन वाली साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं। कॉटन साड़ी के साथ यह ज्वेलरी पहनने पर काफी अच्छी लगेगी। इसमें भी आपका लुक क्लासी लगेगा। इसमें आप चोकर स्टाइल वाली ज्वेलरी खरीदें और साड़ी के साथ पेयर करके पहनें। इसमें आपका लुक अच्छा लगेगा। आप मार्केट से 300-400 रुपए तक में इस तरह के ज्वेलरी सेट खरीद सकते हैं।

## मिरर वर्क वाली ज्वेलरी

आप मिरर वर्क वाली ज्वेलरी को भी कॉटन साड़ी के साथ वियर कर सकती हैं। इस तरह की ज्वेलरी कॉटन साड़ी के साथ काफी अच्छी लगती है। इसको पहनने के बाद लुक भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस ज्वेलरी में छोटे-छोटे डिजाइन में मिरर वर्क मिलेगा। इसके अलावा आपको कलर वाला डिजाइन भी मिलेगा। इस ज्वेलरी को आप मार्केट 200-300 रुपए में खरीद सकती हैं।

# अनारकली सूट में दिखना है स्टनिंग तो अपनाएं ये फैशन हैक्स

जब भी किसी वेडिंग फंक्शन या फैमिली पार्टी के लिए तैयार होने की बात होती है तो अक्सर हम सभी एथनिक वियर पहनना पसंद करती है। इन एथनिक वियर में अनारकली सूट भी एक बेहतरीन एथनिक वियर ऑप्शन माना जाता है। यह एक ऐसा आउटफिट है, जो आपको एलीगेंट लेकिन रॉयल लुक देता है और शायद यही वजह है कि हर लड़की की वार्डरोब में अनारकली सूट होता ही है।

यूं तो अनारकली सूट को ऐसे ही कैरी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ आसान फैशन हैक्स को अपनाया जाए तो आप एक ही सूट को हर बार एक अलग तरह से कैरी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, सिंपल सा अनारकली सूट भी आपके लुक को काफी एन्हॉन्स कर सकता है। अनारकली सूट को स्टाइल करते समय बस आपको कुछ छोटे-छोटे टिप्स पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बारे में आज हम आपको इस लेख में बता रहे हैं-

## दुपट्टे को यूं करें स्टाइल

अनारकली सूट के साथ दुपट्टा कैरी करते समय थोड़ा स्मार्टली प्ले करें। मसलन, अगर अनारकली पर हैवी एंब्रायडरी है, दुपट्टा लाइट रखें। वहीं, अगर अनारकली सिंपल या एक रंग की है, तो उस पर बनारसी, फुलकारी, गोटा-पट्टी या मिरर वर्क वाला दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। आप दुपट्टे को एक तरफ कंधे पर पिन कर दो और दूसरी तरफ ढीला छोड़ दो। इससे एक रॉयल लुक मिलता है। या फिर अगर आप चाहें तो कमर पर बेल्ट लगाकर दुपट्टा फिक्स किया जा सकता है। यह ना केवल स्टाइलिश लगता है, बल्कि दुपट्टे को मैनेजर करना भी आसान हो जाता है।

## फुटवियर पर करें फोकस

जब आप अनारकली सूट पहन रही हैं तो उसके साथ हील्स को जरूर पहनें। फ्लैट्स से अनारकली में आपकी हाइट कम महसूस हो सकती है। अगर आप पेंसिल हील्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे में ब्लॉक हील्स, मोजड़ी हील्स या कोल्हापुरी वेजेस पहने जा सकते हैं। वहीं, अगर आपको इसे लंबे टाइम तक पहनना है, तो कुशन वाले प्लेटफॉर्म हील्स को चुना जा सकता है। यह आपको कंफर्ट और ग्रेस दोनों देगा।

*अनारकली सूट के साथ दुपट्टा कैरी करते समय थोड़ा स्मार्टली प्ले करें। मसलन, अगर अनारकली पर हैवी एंब्रायडरी है, दुपट्टा लाइट रखें। वहीं, अगर अनारकली सिंपल या एक रंग की है, तो उस पर बनारसी, फुलकारी, गोटा-पट्टी या मिरर वर्क वाला दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है।*

## समझदारी से स्टाइल करें ज्वेलरी

अनारकली सूट के साथ एक्सेसरीज को थोड़ा स्मार्टली कैरी करना चाहिए। मसलन, अगर अनारकली सूट की नेकलाइन हाई है तो ऐसे में नेकपीस पहनने से बचें। इसकी जगह बस आप बड़े झुमके या चांदबालियां स्टाइल कर लें। वहीं, अगर नेकलाइन डीप है, तो सिंपल पेंडेंट और छोटे स्टड्स भी काफी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा, दोनों हाथों को चूड़ियों से भरने की गलती ना करें। एक हाथ में स्टेटमेंट कड़ा रखो, दूसरे में वॉच।

# नैनीताल के पास बसा मुक्तेश्वर जन्नत से नहीं है कम

**दिल्ली से करीब 300 किमी की दूरी पर नैनीताल स्थित है। ऐसे में आज हम आपको उत्तराखंड की हसीन वादियों में स्थित मुक्तेश्वर की खासियत से लेकर इसकी खूबसूरती और आसपास में स्थित कुछ बेहतरीन और शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।**

दिल्ली से करीब 300 किमी की दूरी पर नैनीताल स्थित है। जोकि उत्तराखंड का फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशन है। गर्मी से लेकर मानसून के समय भी दिल्ली एनसीआर वाले नैनीताल में वीकेंड पर जाते हैं।

नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन जब पर्यटक नैनीताल मौज-मस्ती के लिए पहुंचते हैं, तो सिर्फ नैनीताल की फेमस जगहों को एक्सप्लोर करके चले जाते हैं।

अरुण मिश्रा

लेकिन यहां से काफी पास में स्थित मुक्तेश्वर जैसी अद्भुत जगह को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं।

ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उत्तराखंड की हसीन वादियों में स्थित मुक्तेश्वर की खासियत से लेकर इसकी खूबसूरती और आसपास में स्थित कुछ बेहतरीन और शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

## उत्तराखंड में मुक्तेश्वर

मुक्तेश्वर नैनीताल जिले में स्थित एक खूबसूरत और मनमोहक गांव है। जोकि मुख्य शहर से करीब 48 किमी दूर है। हालांकि मुक्तेश्वर को कई लोग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मानते हैं। यह अल्मोड़ा से करीब 42 किमी दूर स्थित है। वहीं भीमताल से यह जगह 42 किमी दूर है।

## क्यों फेमस है मुक्तेश्वर

मुक्तेश्वर गांव उत्तराखंड की हसीन वादियों में स्थित है और कई खास चीजों के लिए फेमस है। मुक्तेश्वर सबसे ज्यादा मुक्तेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान शंकर ने इस जगह एक राक्षस का वध किया था। यहां की पौराणिक मान्यताओं के अलावा शांत और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। मुक्तेश्वर, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा की तुलना में कम भीड़-भाड़ वाली जगह है। यहां पर आप घने जंगल, बादलों से ढके ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घास के मैदान और झील-झरने मुक्तेश्वर की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं।

## मुक्तेश्वर पर्यटकों के लिए है खास

पर्यटकों के लिए मुक्तेश्वर किसी जन्नत से कम नहीं है। खासकर यहां की प्राकृतिक सुंदरता

पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। यहां पर आपको नैनीताल से काफी कम भीड़ मिलेगी। इसलिए एकांत की तलाश करने वाले लोगों के लिए मुक्तेश्वर जन्नत से कम नहीं है। आप यहां की खूबसूरती को निहारने के साथ ही एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर की वादियों में रॉक क्लाइम्बिंग से लेकर रैपलिंग, कैंपिंग और ट्रेकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।

## घूमने की बेस्ट जगहें

### मुक्तेश्वर मंदिर

मुक्तेश्वर में पहुंचकर आप सबसे पहले मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जोकि भगवान शिव को समर्पित है। आप यहां पर ट्रेकिंग करके पहुंच सकते हैं।

### चौली की जाली

चौली की जाली को नेचर लवर्स के लिए जन्नत माना जाता है। आप यहां से हिमालय की खूबसूरती को करीब से निहार सकते हैं।

### भालू गढ़ वॉटरफॉल

मुक्तेश्वर से कुछ ही किमी की दूरी पर भालू गढ़ वॉटरफॉल एक फेमस पिकनिक स्पॉट है। बारिश के मौसम में इस वॉटरफॉल की खूबसूरती देखने लायक होती है।

### ऐसे पहुंचे नैनीताल से मुक्तेश्वर

बता दें कि नैनीताल से मुक्तेश्वर पहुंचना बेहद आसान है। इसके लिए आप नैनीताल बस स्टैंड से टैक्सी या फिर कैब से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आप रेंट पर स्कूटी लेकर भी मुक्तेश्वर पहुंच सकते हैं।

# इन कारणों से बढ़ता है नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल, जाने एक्सपर्ट की राय

डॉ. मुकुल शर्मा

*बैड कोलेस्ट्रॉल खून को जमाकर नसों को ब्लॉक कर देता है। जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तले-भुने खाने से नहीं बल्कि अन्य कई चीजों से भी बढ़ता है।*

आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक आम समस्या बन गया है। खानपान से लेकर अनियमित लाइफस्टाइल तक ऐसी कई वजहें हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण बन सकती है। नसों में गंदे कोलेस्ट्रॉल के जमने का सीधा असर दिल पर होता है। जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा फैटी पदार्थ है, जोकि आपके खून में पाया जाता है। जहां पर गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के कई फंक्शन्स के लिए जरूरी होता है।

वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल खून को जमाकर नसों को ब्लॉक कर देता है। जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तले-भुने खाने से नहीं बल्कि अन्य कई चीजों से भी बढ़ता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

## कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण

बता दें कि नसों में कई वजहों से गंदा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो कई बार सही लाइफस्टाइल और डाइट के बाद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।

वहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा महिलाओं में अधिक रहता है। खासकर मेनोपॉज के आसपास भी इसके बढ़ने की संभावना अधिक रहती है।

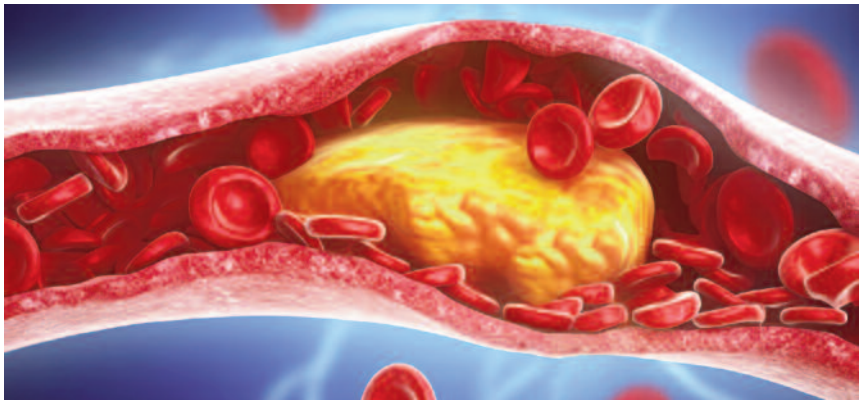

वहीं अगर आप सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स से भरपूर डाइट लेती हैं, तो इससे भी आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। वहीं हाई सैचुरेटेड डाइट लेना इसकी बड़ी वजह है।

वहीं यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। तब भी आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक वजह मोटापा भी है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अधिक चांसेज होते हैं।

मोटापे के कारण शुगर, हाई बीपी और शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या हो सकती है। यह दिन से जुड़ी बीमारियों की भी वजह बन सकता है।

कई बार उम्र बढ़ने के साथ भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ अपना ख्याल रखना जरूरी हो जाता है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को यह समस्या रही है, तो आपको भी यह परेशानी हो सकती है।

फैटी लिवर होने पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक रहती है।

# कई बीमारियों को मैनेज करने में रामबाण की तरह काम करता है लौकी का जूस

*लौकी के रस में भरपूर मात्रा में पानी, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज तक में असरदार हैं। साथ ही साथ, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं तो भी यह एक अच्छा ऑप्शन है।*

कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी डाइट पर खास ध्यान दिया जाए। ऐसी कई सब्जियां होती हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इन्हीं में से एक है लौकी। जिसे आप बतौर जूस ले सकते हैं। अगर सुबह खाली पेट इसका एक गिलास पिया जाए तो इससे ना केवल शरीर अच्छे से डिटॉक्स होता है, बल्कि पाचन सुधरता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है।

दरअसल, लौकी के रस में भरपूर मात्रा में पानी, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज तक में असरदार हैं। साथ ही साथ, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं तो भी यह एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि लौकी का जूस पीने से आप किन स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने में काफी मदद मिल सकती है-

## हाईबीपी

जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत रहती है, उन्हें लौकी के जूस को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दरअसल, इसमें पोटैशियम अच्छा खासा होता है, जो शरीर में सोडियम को बैलेंस करता है और नसों को रिलैक्स करता है। यही वजह है कि सुबह खाली पेट एक गिलास बिना नमक वाला ताजा लौकी जूस पीने से उन्हें काफी फायदा मिलता है।

## डायबिटीज

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो भी आप लौकी के जूस को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। दरअसल, लौकी का जूस न ज्यादा कैलोरी वाला होता है और न ही मीठा, इसलिए यह शुगर कंट्रोल के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ, इसमें फाइबर होता है जो खाने को धीरे-धीरे पचने देता है, जिससे आपको ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। इससे इंसुलिन सेंसेटिविटी भी बेहतर होती है।

## कब्ज और गैस

जिन लोगों का पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता या उन्हें दिनभर गैस आदि की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लौकी का जूस पीना चाहिए। ये पेट को ठंडक देता है। साथ ही साथ, फाइबर रिच होने की वजह से आपकी कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। पाचन के लिए लौकी का जूस काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतों से भी राहत मिलती है।

## लिवर की समस्या

अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसे में आपको लौकी का जूस पीना चिहए। लौकी का जूस लिवर को डीटॉक्स करता है। साथ ही साथ, इससे लिवर को ठंडक मिलती है और यह फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम में भी सपोर्ट करता है। रोज पीने से लिवर की सेहत सुधरती है।

# मिस वर्ल्ड का खिताब जीत इंडस्ट्री में आईं ये हीरोइन, कैसा रहा फिल्मी करियर?

आकांशा गर्ग

**अक्सर कहा जाता है कि फैशन की दुनिया का रास्ता फिल्म इंडस्ट्री में जाकर खुलता है। बात अगर सौंदर्य प्रतियोगिताओं की करें तो इन्हें जीतने वाली सुंदरियां फिल्मों में करियर बनाने का रुख करती हैं और कई पूर्व मिस वर्ल्ड बॉलीवुड में काम कर रही हैं।**

सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली और खिताब अपने नाम करने वाली तमाम सुंदरियों का सपना अभिनय की दुनिया में नाम कमाने का होता है। ऐसा होता भी आ रहा है। फिलहाल बात साल 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की करते हैं। फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से उन्होंने साल 2022 में डेब्यू किया। इन दिनों वे 'मालिक' में नजर आ रही हैं। उनसे पहले और भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत चुकीं कई भारतीय सुंदरियों ने सिनेमा की दुनिया में एंट्री ली। जानते हैं किसका करियर कैसा रहा है?

## रीता फारिया

रीता फारिया यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला हैं। उन्होंने फिल्म और मॉडलिंग के बजाय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला किया। हालांकि, शुरूआती एक साल उन्होंने मॉडलिंग जरूर की, लेकिन फिर पूरा ध्यान अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पर दिया। बता दें कि वे साल 1966 में मिस वर्ल्ड रहीं।

## ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। उन्होंने इंडस्ट्री में करियर बनाया और उनका करियर सफल रहा है। उन्होंने साउथ फिल्म 'इरुवर' से डेब्यू किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'और प्यार हो गया' (1997) है। ऐश्वर्या राय का नाम सिनेमा की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बच्चन परिवार की बहू हैं। अभिषेक बच्चन से उन्होंने शादी की है।

## डायना हेडन

डायना हेडन ने साल 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज पहना। वे बतौर इवेंट मैनेजर काम करती हैं। 2008 में वे रियलिटी शो बिग बॉस में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में दिखीं।

## युक्ता मुखी

युक्ता मुखी साल 1999 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। वे कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। युक्ता मुखी ने साल 2001 में तमिल फिल्म 'पूवेल्लम उन वसम' से डेब्यू किया। साल 2002 में आफताब शिवदासानी के साथ 'प्यासा' के जरिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। साल 2019 में उन्हें फिल्म 'गुड न्यूज' में देखा गया।

## मानुषी छिल्लर

अब बात करें साल 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली मानुषी छिल्लर की तो उन्होंने साल 2022 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से डेब्यू किया। यह फिल्म फ्लॉप रही। फिर वे द ग्रेट इंडियन फैमिली, बड़े मियां छोटे मियां में नजर आईं और ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। फिलहाल वे राजकुमार राव के साथ 'मालिक' में नजर आ रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।

## प्रियंका चोपड़ा

साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनीं। सिनेमा की दुनिया में उन्होंने क्या नाम कमाया है, इससे दुनिया वाकिफ है। वे बॉलीवुड की देसी गर्ल हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड तक उनका डंका बज रहा है। निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा विदेश में शिफ्ट हो गई हैं।

# मिस यूनिवर्स बनीं भारतीय सुंदरियों का करियर

अब तक तीन भारतीय महिलाओं ने मिस यूनिवर्स खिताब अपने नाम किया है। साल 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनीं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने खूब नाम कमाया है। साल 2000 में लारा दत्ता मिन यूनिवर्स बनीं। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि, फिलहाल वे इंडस्ट्री से दूर हैं। उन्होंने टेनिस स्टार महेश भूपति से शादी रचाई है। साल 2021 में हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। वे सिनेमा में एंट्री ले चुकी हैं, मगर अभी पंजाबी इंडस्ट्री तक सीमित हैं। फिल्म 'बागी 4' से वे बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं।

# 5 बल्लेबाज जिन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन

महमूद रजा
बिजनौर

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है। गेंदबाज रेड बॉल के साथ बल्लेबाजों के संयम और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। व्हाइट बॉल की तुलना में लाल बॉल ज्यादा सीम और स्विंग करती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए आसानी से रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी

430 – शुभमन गिल
344 – सुनील गावस्कर
340 – वीवीएस लक्ष्मण
330 – सौरव गांगुली
319 – वीरेंद्र सहवाग

**आज हम आपको एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं। भारत के लिए हाल ही में शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर को पछाड़कर एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।**

1 – **शुभमन गिल :** भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम दर्ज है। उन्होंने एक टेस्ट की पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाए। गिल 430 रनों के साथ एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने 2 से 6 जुलाई तक एजबेस्टन में खेले गए भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी।

2 – **सुनील गावस्कर :** टीम इंडिया पूर्व कप्तान और दाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील गावस्कर भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। गावस्कर ने अप्रैल 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 220 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कुल एक मैच में 344 रन बनाए।

3 – **वीवीएस लक्ष्मण :** इंडियन क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भारत के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। लक्ष्मण ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह खास उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने पहली पारी में 59 और दूसरी पारी में 281 रन बनाकर कुल 340 रनों का स्कोर अपने नाम किया था।

4 – **सौरव गांगुली :** भारत के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पहचाने जाने वाले सौरव गांगुली भी इस लिस्ट में शामिल हैं। गांगुली भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में पहली पारी में 239 और दूसरी पारी में 91 रन बनाए थे। इस टेस्ट में उनके बल्ले से कुल 330 रन निकले थे।

5 – **वीरेंद्र सहवाग :** भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। सहवाग ने 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 319 रनों की पारी खेली थी। वो 319 रनों के साथ भारत के लिए एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं।

HET

Once You
Buy The

# Solar

The Power is Free

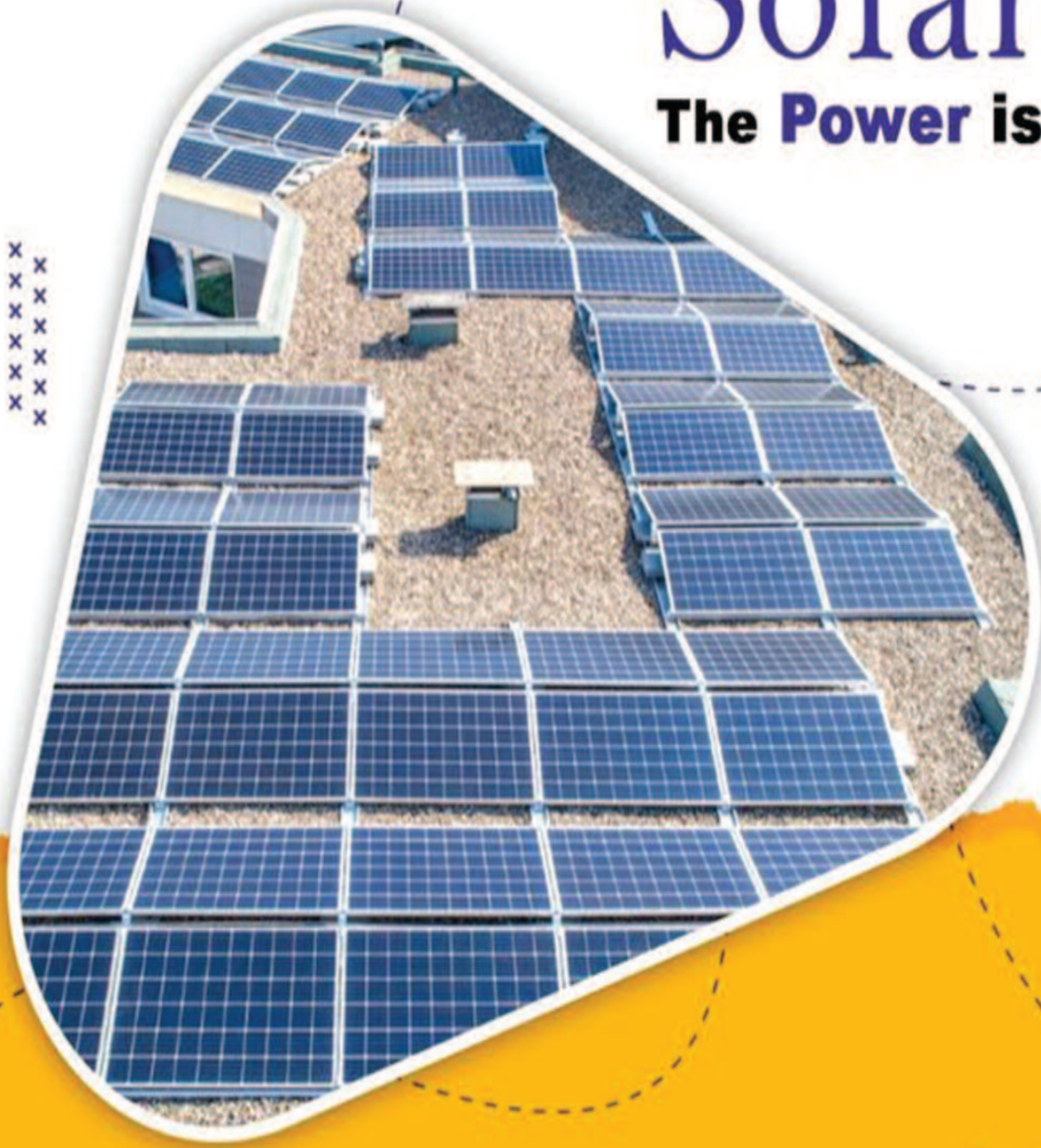

## Harshita Electro & Telecom Pvt. Ltd.

SOLAR ON-GRID ROOFTOP SOLUTIONS | OFF GRID SOLAR SYSTEM
HYBRID SOLAR SYSTEM

Office : GF-135, Durga Tower, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad.
Phone : 9891116568, 9891116569, 9899562233

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

*Assuring Excellence in Bath Faucets*

**SHANTI NATH MANUFACTURERS**
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

# यूपी बन रहा टेक्नो-हब

- 6 विभागों में AI कौशल उन्नयन, 10 लाख लोग होंगे प्रशिक्षित
- महाकुम्भ-2025 की अभेद्य सुरक्षा में AI का व्यापक उपयोग
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में 4 लाख+ रोजगार के अवसर

- जेवर में ₹3,700 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू
- यूपी की GDP में IT सेक्टर का 3.2 प्रतिशत योगदान
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी निर्यात में तीव्र वृद्धि
- नोएडा, लखनऊ एवं कानपुर में टेक्नोलॉजी हब
- AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं साइबर सिक्योरिटी का उन्नयन
- देश के 45% स्मार्टफोन एवं 55% मोबाइल पार्ट्स का निर्माण यूपी में

**सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क**

**6 शहरों में स्थापित**

**3 शहरों में निर्माणाधीन**

## काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP